

हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

haribhoomi.com

बिलासपुर, गुरुवार 6 मार्च 2025



प्रगति
CG बजट 2025-26

स्वास्थ्य सेवाओं को देने वाला बजट

ChhattisgarhCMO | DPRChhattisgarh | www.dprcg.gov.in

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ₹1,850 करोड़
शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना ₹1,500 करोड़
आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना ₹182 करोड़
मुख्यमंत्री स्वस्थ योजना ₹100 करोड़



श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सुशासन से समृद्धि तक

660 करोड़ के घोटाले में पहली बार आईएस से पूछताछ, ईओडब्लू के अफसरों ने छह घंटे तक दागे सवाल

हरिभूमि न्यूज | रायपुर

रीएजेंट और उपकरणों की सप्लाई की आड़ में हुए 660 करोड़ के महाघोटाले में पहली बार सीजीएमएससी के पूर्व एमडी एवं आईएस अफसर चंद्रकांत वर्मा से ईओडब्लू की टीम ने पूछताछ की है। कार्पोरेशन में हुए दस्तावेजों की छानबीन गिरफ्तार मोक्षित कार्पोरेशन के एमडी से मिली जानकारी के आधार पर लगभग 6 घंटे तक उन पर कई तरह के सवाल दागे गए हैं। मामले में जल्दी ही ईओडब्लू द्वारा दूसरी बड़ी कार्रवाई किए जाने की संभावना है। इस मामले से जुड़े मोक्षित कार्पोरेशन के एमडी



दूसरे बड़े एक्शन की तैयारी, मोक्षित कार्पोरेशन का एमडी अभी जेल में

खराब हो रही दवाओं पर चुप्पी

इस प्रकरण में स्वास्थ्य केंद्रों में सप्लाई किया गया करोड़ों का केमिकल खराब हो चुका है और उतने की एक्स्पायर होने की स्थिति में है। सप्लाई हुए सीबीसी सहित अन्य मशीनों का उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। इन उपकरणों और रीएजेंट के सद्बुधयोग के दावे वर्तमान अधिकारियों द्वारा किया गया था मगर अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य केंद्रों तक जरूरी रीएजेंट और दवाओं की सप्लाई अब तक सामान्य नहीं हो पाई है।



महाघोटाले में कार्पोरेशन के साथ स्वास्थ्य विभाग के कई अफसर घेरे में

न्यायिक रिमांड पर जेल

जनवरी के अंतिम दिनों में विभिन्न ठिकानों में छापेमारी के बाद गिरफ्तार मोक्षित कार्पोरेशन के एमडी शशांक चोपड़ा अभी न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं। 24 फरवरी को उसकी न्यायिक रिमांड की अवधि बढ़ाई गई थी। उसकी अगली पेशी 9 मार्च को होगी।

नहीं हटे अफसर

सीजीएमएससी में काम कर कुछ अफसरों को ईओडब्लू की जांच का हवाला देकर हटाने की सिफारिश की गई थी। विभागीय सहमति मिलने के बाद भी अब तक वे दवा कार्पोरेशन में अपनी सेवा दे रहे हैं। इन अफसरों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर नए लोगों को जिम्मेदारी देने के मामले को ऊपरी दबाव के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसके अलावा सीजीएमएससी कार्यालय अभी भी कड़ी सुरक्षा में है। कार्यालय से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी के अलावा अन्य लोगों को भीतर घुसने पर मनाही है।

शशांक चोपड़ा जेल में हैं। सूत्रों के मुताबिक ईओडब्लू की टीम ने काफी दिनों तक चोपड़ा से मिली जानकारी के आधार पर सीजीएमएससी के कार्यालय जाकर दस्तावेजों को खंगालती रही। इस प्रकरण में कई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता सामने आ चुकी है। दवा कार्पोरेशन से कुछ महीने पहले हटाई गई एक महिला अधिकारी कई बार ईओडब्लू के चक्कर लगा चुकी है। इस मामले में सीजीएमएससी के तात्कालीन एमडी एवं आईएस अधिकारी चंद्रकांत वर्मा को तलब किया गया था। दो दिन पहले उन्हें ईओडब्लू के कार्यालय में हुई गडबडी के मामले में लंबी पूछताछ हुई है। स्वास्थ्य विभाग के इस सबसे बड़े घोटाले में दवा कार्पोरेशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य संचालनालय से जुड़े कई अफसर शामिल हैं।

खबर संक्षेप

फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से

लाहौर। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका सामना भारतीय टीम से दुबई के मैदान पर 9 मार्च को होगा। बुधवार को

लाहौर में न्यूजीलैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 50 रन से हराया। 363 रन का टारगेट चेज कर रही अफ्रीकी टीम 9 विकेट पर 312 रन ही बना सकी।

छह दिवसीय वार्षिक साहित्योत्सव कल से

नई दिल्ली। साहित्य अकादमी का छह दिवसीय वार्षिक साहित्योत्सव 7 मार्च से शुरू हो रहा है। इस दौरान 100 से अधिक सत्रों में 700 से ज्यादा

विख्यात लेखक और विद्वान भाग लेंगे। सात मार्च को इस साहित्योत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे।

वरिष्ठ आईएस जीईएम का सीईओ नियुक्त

नई दिल्ली। सरकार ने वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव अजय

भादू को सार्वजनिक खरीद मंच जीईएम का सीईओ नियुक्त किया है। वह विभाग में अपनी मौजूदगी जिम्मेदारियों के अलावा यह भूमिका भी संभालेंगे।

सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल नौ अगस्त, 2016 को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए शुरू किया गया था।

बारामुला में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के बारामुला जिले में आतंकवादियों ने

पुलिस की एक चौकी पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। हालांकि, इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। मंगलवार रात करीब नौ बजकर 20 मिनट पर बारामुला के ओल्ड टाउन स्थित पुलिस चौकी के पास से विस्फोट की आवाज आवाज आई, जिससे लोग भयभीत हो गए।

एसडीएम-पटवारी ने मिलीभगत कर दस्तावेज में किया हेरफेर, शासन को लगाया चूना भारतमाला...बड़ा घोटाला, विस में गूंजा एसडीएम के बाद अब तहसीलदार सस्पेंड

हरिभूमि न्यूज | रायपुर

बताया गया है कि मुआवजा बांटने के नाम पर अधिकारियों ने पैसों की बंदरबाट की। कई जमीनों का खसरा बदल दिया गया। कुछ जगहों पर पूर्व खसरे पर राशि का भुगतान कर दिया गया। अफसरों ने दस्तावेजों में हेर-फेर कर भू-माफिया की मदद से करोड़ों रुपए की अफरातफरी की थी। अभनपुर के ग्राम नायकबांधा और उरला में भू-माफिया ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर 159 मीटर जमीन की कोमत करीब 29.5 करोड़ से बढ़कर 78 करोड़ रुपए पहुंच गई। अभनपुर में 9.38 किलोमीटर के लिए 324 करोड़ रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया था। मामले में शेष पेज 6 पर

246 करोड़ का मुआवजा बांट

अभनपुर के ग्राम नायकबांधा और उरला में भू-माफिया ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर 159 मीटर जमीन की कोमत करीब 29.5 करोड़ से बढ़कर 78 करोड़ रुपए पहुंच गई। अभनपुर में 9.38 किलोमीटर के लिए 324 करोड़ रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया था। मामले में शेष पेज 6 पर



सर्वे के ठीक पहले ही जमीन का बंटवारा

जांच टीम ने अभनपुर इलाके में पदस्थ अधिकारियों ने बैंक डेट में जाकर दस्तावेजों में गडबडी की और जमीन मालिक को नुकसान पहुंचाया। इसका खुलासा इस बात से अफसरों ने किया कि अभनपुर के ग्राम नायकबांधा और उरला में चार एकड़ जमीन जो सर्वे से पहले एक परिवार के पास थी, वो सर्वे होने के ठीक कुछ दिन पहले एक ही परिवार के 14 लोगों के नाम में शेष पेज 6 पर

भारतमाला प्रोजेक्ट रायपुर में 48.73 किलोमीटर होगी

भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुंबई-कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क पर दुर्ग-रायपुर बाइपास का निर्माण किया जाना है। चार और छह लेन की यह सड़क छत्तीसगढ़ में कुल 92.230 किमी लंबाई की होगी। यह सड़क राजनांदगांव जिले के टेडेसरा गांव से शुरू होकर रायपुर जिले के पारानांव में समाप्त होगी। रायपुर जिले में सड़क की कुल लंबाई 48.73 किमी होगी। सड़क में अभनपुर अनुभाग के शेष पेज 6 पर

डी. रमन ने इसे अत्यंत खेदजनक बताया है। अधिकारियों से कहा- सनल पद दे नवाब

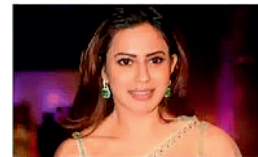
भारतमाला प्रोजेक्ट का जवाब आधे घंटे पहले मिलने पर बिफरे महंत



छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतमाला परियोजना में प्रभावितों को मुआवजा में गडबडी मामले में नेता प्रतिपक्ष डी. चरण दास महंत ने अध्यक्ष के निर्देश के बावजूद प्रश्न का उत्तर आधे घंटे पहले मिलने पर आपत्ति जताई। उन्होंने व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए कहा, मुझे प्रश्न का उत्तर अभी आधे घंटे पहले मिला, इसे इतनी देर में पढ़ा भी नहीं जा सकता। यह पिछले हफ्ते का प्रश्न था, जिसने आज के लिए लेना तय शेष पेज 6 पर

12 करोड़ के सोने की तस्करी

रान्या बोली-तस्करी के लिए किया ब्लैकमेल



हरिभूमि न्यूज | नई दिल्ली

डीजीपी पिता बोले-हैरान और हताश

मामले पर रान्या राव के पिता और कर्नाटक राज्य पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के डीजीपी रामचंद्र राव ने कहा, जब मीडिया के जरिए ऐसी घटना मेरे संज्ञान में आई तो मैं भी हैरान और हताश हो गया। मुझे इनमें से किसी भी चीज के बारे में पता नहीं था, किसी भी दूसरे पिता की तरह मैं भी हैरान था। वो हमारे साथ नहीं रह रही है, वो अपने पति के साथ अलग रह रही है।

रान्या क्यों थी शक के घेरे में? सूत्रों के अनुसार, रान्या राव पिछले कुछ महीनों में कई बार खाड़ी देशों के छोटे-छोटे ट्रिप पर जा रही थीं। उनकी इन शॉर्ट विजिट्स पर पहले से ही डीआरआई की नजर थी। लगातार विदेश यात्राओं और संदिग्ध गतिविधियों के कारण उन पर पहले से ही शक था और आखिरकार उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

जिपं दुर्ग में बड़ा ड्रामा, कांग्रेस की उम्मीदवार गायब भाजपा प्रत्याशी ने दर्ज की निर्विरोध जीत

हरिभूमि न्यूज | दुर्ग

जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पूरा समीकरण बनाकर नामांकन भरने पहुंचे कांग्रेस के नेताओं को उल्टे पांव लौटना पड़ा गया। नामांकन दाखिल करने के पहले ही कांग्रेस की उम्मीदवार गायब हो गई। जिससे संगठन से लेकर राज्य स्तर के नेताओं के बीच खलबली मच गई। हालात यह रहे कि शेष पेज 6 पर



■ जिला पंचायत आने से पहले उषा सोनवानी गायब, थाने में शिकायत
■ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा के उम्मीदवारों ने दर्ज की जीत

थाने में की शिकायत

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष निर्मल कोसरे ने बताया कि उनके सभी सदस्य रात को उनके साथ ही थे। सुबह सीधे जिला पंचायत जाने की बात हुई थी। इस बीच सुबह उषा सोनवानी गायब हो गई। उन्होंने बताया कि उनके परिजन ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है।

मणिपुर में लगातार दो बार भूकंप के झटके

शि लांग / इंफाल / गुवाहाटी डी। मणिपुर में दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनमें से एक भूकंप की तीव्रता 5.7 थी। भूकंप के झटके पूरे पूर्वोत्तर में महसूस किए गए। शिलांग में क्षेत्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के अनुसार, राज्य में पूर्वोत्तर 11 बजकर छह मिनट पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र इंफाल पूर्वी जिले के थारिपोक से 44 किलोमीटर पूर्व में और 110 किलोमीटर की गहराई पर था। उन्होंने बताया कि भूकंप के झटके असम, मेघालय और क्षेत्र के अन्य हिस्सों में महसूस किए गए।

अलग-अलग जिलों के स्कूल के आधा दर्जन शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई

आधा दर्जन शिक्षकों के तबादले का फर्जी आदेश

हरिभूमि न्यूज | रायपुर

स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर अलग-अलग जिलों में आधा दर्जन शिक्षकों के ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने इसकी लिखित शिकायत राखी थाने में दर्ज कराई है। शिकायत पर पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। फर्जी हस्ताक्षर कर ट्रांसफर जारी करने वाले अज्ञात के खिलाफ पुलिस गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव के नाम से फर्जी ट्रांसफर सूची जारी करने में शेष पेज 6 पर

फर्जी ट्रांसफर आदेश में यह है शिक्षकों का फर्जी ट्रांसफर आदेश जारी किया गया है, वह हबहब सरकारी आदेश की ओर जलन आदेश कोपी की तरह है। आदेश कोपी में क्रमांक एफ 3-27/2025/20 - तीन राज्य शासन एतद द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवकों का स्थानांतरण उनके नाम के सम्मुख करते हुए शेष पेज 6 पर

ऐसा पहली बार जब पत्नी जीती और पति ने ली शपथ महिला पंचों की गैर मौजूदगी में उनके पतियों को शपथ दिलाने पर गिरी गाज

हरिभूमि न्यूज | कवर्धा

नवनिर्वाचित पंच प्रतिनिधियों के प्रथम सम्मेलन में महिला पंचों के अनुपस्थिति में उनके पतियों को नियम विरुद्ध पंच पद का शपथ दिलाए जाने वाले



पंचायत सचिव को जांच के बाद तत्काल प्रभाव से निर्वाचित कर दिया गया है। दोषी ग्राम पंचायत परसवारा के सचिव प्रणीवर शेष पेज 6 पर

जांच में माना गया दोषी

इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया द्वारा प्रथम दृष्टया सचिव को दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रणवीर सिंह ठाकुर को निर्वाचित करते हुए जनपद शेष पेज 6 पर

हरिभूमि ने प्रमुखता से उठाया था मामला

ग्राम पंचायत परसवारा के सचिव द्वारा नवनिर्वाचित पंच प्रतिनिधियों के प्रथम सम्मेलन में महिला पंचों के अनुपस्थिति में उनके पतियों को नियम विरुद्ध पंच पद की शपथ दिलाए जाने के मामले को हरिभूमि ने बुधवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसे संज्ञान में लेते हुए प्रशासन द्वारा यह कार्यवाई की गई।

www.shreegururaji.com

Gururaji
Sawal bhi... Sebat bhi...

होली आई, तो लाओ गुरुजी ठण्डाई

अब 400ml और 200ml के छोटे पैक में भी उपलब्ध

FOR ENQUIRY: 88151 00914, 97709 00621, 97709 00616

खबर संक्षेप

रतन टाटा के नाम से होगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी

गुवाहटी। असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।



कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास में स्वर्गीय रतन टाटा और टाटा समूह की भूमिका को मान्यता देने के लिए जगदीश चंद्र इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखने का फैसला किया। इस फैसले के बाद सीएम हिमंता ने एक पोस्ट में कहा कि 'राज्य के विकास में स्वर्गीय रतन टाटा और टाटा समूह की जबरदस्त भूमिका और योगदान की मान्यता के रूप में, असम कैबिनेट ने जगदीश चंद्र इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जगदीश चंद्र रखने का फैसला किया है। उद्योगपति-प्रोपकारी रतन टाटा रतन टाटा का 9 अक्टूबर को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा प्रवर्तित सबसे बड़े प्रोपकारी ट्रस्टों में से दो, रतन टाटा ट्रस्ट और दौलतजी टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। उन्हें 2008 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

गोधरा कांड के 14 गवाहों की हटाई गई सुरक्षा नई दिल्ली। गुजरात के बहुचर्चित गोधरा कांड के गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है। केंद्र सरकार ने यह फैसला गुड मंत्रालय की सिफारिश के बाद लिया है। सुरक्षा के मुताबिक, कुल 14 गवाहों की सुरक्षा वापस ले ली गई है, जिन्हें पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 150 जवानों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। गुड मंत्रालय ने इस निर्णय के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) की रिपोर्ट को आधार बनाया है। एसआईटी ने 10 नवंबर 2023 को अपनी सिफारिश रिपोर्ट सीपी थो, जिसमें गवाहों की सुरक्षा हटाने का सुझाव दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

गोधरा कांड के 14 गवाहों की हटाई गई सुरक्षा

नई दिल्ली। गुजरात के बहुचर्चित गोधरा कांड के गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है। केंद्र सरकार ने यह फैसला गुड मंत्रालय की सिफारिश के बाद लिया है।



सुरक्षा के मुताबिक, कुल 14 गवाहों की सुरक्षा वापस ले ली गई है, जिन्हें पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 150 जवानों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। गुड मंत्रालय ने इस निर्णय के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) की रिपोर्ट को आधार बनाया है। एसआईटी ने 10 नवंबर 2023 को अपनी सिफारिश रिपोर्ट सीपी थो, जिसमें गवाहों की सुरक्षा हटाने का सुझाव दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

मायावती ने भतीजे के बाद भाई से भी वापस लिया पद

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। पहले उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त किया तो उसके दूसरे दिन पार्टी से बाहर का सभा दिया दिया। भतीजे के बाद अब मायावती की गाज अपने भाई पर गिरी है। उन्होंने आनंद कुमार को राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दिया है। अब वे केवल उपाध्यक्ष रहेंगे।

राशिफल

मेघ	दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। परिवार की सुख-सुविधाओं के लिए खर्च बढ़ेगा। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा।
वृष	मन प्रसन्न तो रहेगा। परन्तु बातचीत में संयत रहें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सुखादुःख खानपान में रुचि बढ़ सकती है।
मिथुन	व्यर्थ के क्रोध से बचें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक रहेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखें।
कर्क	परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। भाइयों से मतभेद हो सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें।
सिंह	संयत रहें। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद-विवाद से बचें। किसी मित्र के सहयोग से सम्पत्ति में कितना गिरावट लाभाद्र रहेगा। मोटो खानपान में रुचि रहेगी।
कन्या	संयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। कुटुम्ब की किसी बुजुर्ग महिला से घन मिल सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
तुला	वाणी में मधुरता रहेगी। वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। कुटुम्ब-परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि होगी।
वृश्चिक	मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी आयेगी। बातचीत में संयत रहें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी।
धनु	क्रोध के अतिरेक से बचें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। कारोबार में किसी मित्र के सहयोग से लाभ में वृद्धि होगी।
मकर	व्यर्थ के क्रोध से बचें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। बौद्धिक कार्यों में सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत का ध्यान रखें।
कुम्भ	आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा। परन्तु आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ सकती है। धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेंगे।
मीन	मन प्रसन्न रहेगा। कर्मक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

भारत में 2024 में करोड़पतियों की संख्या बढ़कर हुई छह प्रतिशत

एजेंसी नई दिल्ली

वैश्विक रियल एस्टेट परामर्श कंपनी नाइट फ्रैंक ने कहा है कि एक करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले उच्च नेटवर्क भारतीयों की संख्या पिछले साल छह प्रतिशत बढ़कर 85,698 हो गई। नाइट फ्रैंक ने बुधवार को अपनी 'द वैल्यू रिपोर्ट-2025' जारी की। इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत में उच्च नेटवर्क वालों (एचएनडब्ल्यूआई) की संख्या बढ़कर 2024 में 85,698 होने का अनुमान है जबकि पिछले साल यह 80,686 थी। परामर्श कंपनी ने कहा कि 2028 तक यह संख्या बढ़कर 93,753 पर पहुंचने की उम्मीद है।

रियल एस्टेट परामर्श कंपनी नाइट फ्रैंक ने जारी की रिपोर्ट

उच्च नेटवर्क वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही

नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, "भारत में बढ़ती संपत्ति इसकी आर्थिक मजबूती और दीर्घकालीन वृद्धि क्षमता को दर्शाती है। देश में बढ़ती उद्यमशीलता, वैश्विक एकीकरण और उमरते उद्योगों के साथ उच्च नेटवर्क मूल्य वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है।"



संपत्ति सृजन में भारत का प्रभाव होगा मजबूत

बैजल ने कहा कि न केवल संख्या बढ़ रही है बल्कि भारत के इस वर्ग की उमरती निवेश प्रार्थनिकताओं में भी यह देखा जा रहा है, जो रियल एस्टेट से लेकर वैश्विक इतिवृत्त तक परिसंपत्ति वर्गों में विविधता ला रहे हैं। बैजल ने कहा, "आने वाले दशक में वैश्विक संपत्ति सृजन में भारत का प्रभाव और मजबूत होगा।"

अरबपतियों की संपत्ति 950 अरब डॉलर आंकी

भारतीय अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति 950 अरब डॉलर आंकी गई है, जो अमेरिका (5,700 अरब डॉलर) और चीन (1,340 अरब डॉलर) के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।

देश में बढ़ रही अमीरों की संख्या

इससे पता चलता है कि भारत में अमीरों की संख्या बढ़ रही है। उच्च नेटवर्क वाले लोगों की बढ़ती संख्या देश की मजबूत दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश अवसरों और विकसित हो रहे लक्जरी बाजार को दर्शाती है। यह भारत को वैश्विक धन सृजन में एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित करती है।

2019 में सिर्फ सात अरबपति थे

भारत में अरबपतियों की आबादी में भी 2024 में सालाना आधार पर मजबूत वृद्धि हुई है। परामर्श कंपनी ने कहा, "भारत में अब 191 अरबपति हैं। इनमें से 26 पिछले साल ही इस श्रेणी में शामिल हुए हैं। जबकि 2019 में यह संख्या सिर्फ सात थी।"

फिर निकला 38 साल पुराने बोफोर्स का जिन्न

राजीव गांधी सरकार के दौरान सामने आए कथित बोफोर्स घोटाले के मामले की जांच को एक बार फिर खोलने की कवायद तेज हो गई है। भारत सरकार ने अमेरिका से संपर्क किया है और उनसे 1980 के दशक की 64 करोड़ रुपये की बोफोर्स डील के संबंध में अहम जानकारी मांगी गई है।

एजेंसी नई दिल्ली

अमेरिकी न्याय विभाग को भेजा गया है अनुरोध पत्र

स्वीडन से मांगी गई 155 मिमी फ़ील्ड आर्टिलरी गन की डिटेल



रेडियो शो ने खोला घोटाले का राज

बोफोर्स घोटाला स्वीडिश रेडियो द्वारा उजागर किया गया था। इसके बाद साल 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी। यह उनकी हार का बड़ा कारण बना था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप को खारिज कर दिया था लेकिन इसके बावजूद बोफोर्स घोटाले से जुड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं। ये सवाल रिश्वतखोरी के मामले में इटली के व्यवसायी ओटावियो क्वाराजोनी की भूमिका से जुड़े हैं, जिसका राजीव गांधी सरकार के दौरान बहुत दबदबा था।

अब यह चाहती है सीबीआई

सीबीआई ने स्वीडिश हथियार निर्माता एबी बोफोर्स द्वारा भारत से 400 हॉवित्जर का ऑर्डर हासिल करने के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत के संबंध में यूएस-आधारित निजी जासूसी फर्म फेयरफैक्स के प्रमुख माइकल हर्शमैन के पास मौजूद मामले का विवरण मांगा है। 2017 में हर्शमैन ने दावा किया था कि बोफोर्स से रिश्वत का पैसा कथित तौर पर बैंक में जमा कराया गया था। तत्कालीन पीएम राजीव गांधी उस समय गुप्त से थे जब उन्हें स्विस बैंक खाता 'मोट ब्लांक' मिला था। हर्शमैन ने यह भी दावा किया था कि तत्कालीन सरकार ने उनकी जांच को विफल कर दिया था। सीबीआई ने सबसे पहले अक्टूबर में दिल्ली की अदालत से संपर्क किया था, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों से विवरण मांगने की उनकी योजना के बारे में बताया गया था। यह कदम हर्शमैन द्वारा उठाया गया था, जो बोफोर्स मामले में अपनी संप्रतिष्ठा के कारण राजनीतिक हलकों में प्रमुखता से उभरे थे। उन्होंने भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग करने पर सहमति जताई थी।

राहुल पर लगा 200 रुपए जुर्माना, कोर्ट बोला 14 अप्रैल को पेश हों



सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' और 'पेंशन लेने वाला' कहा था

एजेंसी लखनऊ

लखनऊ के कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों, यदि वे इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट कानूनी कार्यवाई हो सकती है। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय के अनुसार, राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' और 'पेंशन लेने वाला' कहा था। शिकायतकर्ता ने कहा- यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पत्र भी पत्रकारों के बीच वितरित किए गए थे। इस बयान को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।

राहुल के वकील बोले

वे विदेशी गणमान्य नागरिक से मुलाकात में व्यस्त सुनवाई के दौरान राहुल को और से वकील प्रशु अचवाल ने अदालत में पेशी से छूट की जर्जी दाखिल की। इसमें उन्होंने दलील दी कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आज (5 मार्च) उनकी अदालत में उपस्थित नहीं हो सकें। वे अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे। अदालत ने बी कड़ी चेतावनी, 14 अप्रैल को पेशी जरूरी अदालत में राहुल गांधी की अनुपस्थिति को हल्के में न लेते हुए 200 रुपए का जुर्माना लगाया और 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।

जयपुर घोषणा पत्र अंगीकृत: एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम

जयपुर। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास को नई दिशा देने वाले ऐतिहासिक क्षण में, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री तोखन साहू ने जयपुर में आयोजित 12वें क्षेत्रीय 3R एवं परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच में भाग लिया। यह मंच एक वैश्विक प्लेटफॉर्म के रूप में विभिन्न देशों को एक साथ लाने और स्वच्छ, हरित और संसाधन-कुशल भविष्य की दिशा में सहयोग करने का अवसर प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान, श्री साहू ने जापान के पर्यावरण मंत्रालय में वैश्विक पर्यावरण मामलों के उपमंत्रि युताका मात्सुजिवा के साथ भारत-जापान द्विपक्षीय संवाद में भाग लिया। इस संवाद में 3R (रिड्यूस, रीयूज, रिसायकल), संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था में भारत-जापान सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई, जिससे सतत विकास के लिए ठोस साझेदारियों की नींव रखी जा सके। इस मंच की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि "जयपुर

सरकुलर इकोनोमी कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है- तोखन साहू



घोषणा पत्र" का अंगीकरण रहा, जो 2025 से 2034 तक सतत अपशिष्ट प्रबंधन और परिपत्र अर्थव्यवस्था पहलों को दिशा देने वाला एक दूरदर्शी दस्तावेज है। जयपुर घोषणा पत्र विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं, संसाधन दक्षता, सतत सामग्री उपयोग, अनौपचारिक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान एवं विकास और बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से इन उद्देश्यों को साकार करने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। भारत में इस मंच में एक वैश्विक गठबंधन C-3 के रूप में एक सहयोगात्मक ज्ञान मंच भी प्रस्तुत किया, जो नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत और शोधकर्ताओं को एक साथ लाकर सतत समाधानों की दिशा में सहयोग को बढ़ावा देगा। अपने दौरे के दौरान, श्री साहू ने इंडिया पवेलियन का भी अवलोकन किया, जहां भारत की 3R और परिपत्र अर्थव्यवस्था अपनाने की दिशा में क्रांतिकारी पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन, स्मार्ट शहरी समाधान और अन्य सतत नवाचारों के माध्यम से भारत के नेतृत्व को उजागर किया गया।

वन्यजीव पुनर्वास केंद्र 'वनतारा' पहुंचे प्रधानमंत्री

जामनगर। वनतारा में 2,000 से अधिक प्रजातियां और 1.5 लाख से अधिक बचाए गए, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जानवर रहते हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्र में विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने वनतारा में वन्यजीव अस्पताल का दौरा किया और पशु चिकित्सा सुविधाओं को देखा, जो एमआरआई, सीटी स्कैन, आईसीयू और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित हैं और यहां वन्यजीव एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी, दंत चिकित्सा, आंतरिक चिकित्सा आदि सहित कई विभाग भी हैं। यहां उन्होंने एशियाई शेर शावकों, संफेद शेर शावक, क्लाउडड तेंदुए शावक जो एक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति के हैं, केराकल क्लब में शावक सहित विभिन्न प्रजातियों को देखा। केंद्र में



बचाए गए जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास के समान स्थानों पर रखा जाता है। केंद्र में किए गए कुछ प्रमुख संरक्षण पहलों में एशियाई शेर, हिम तेंदुआ, एक साँग वाला गैंडा आदि शामिल हैं। पीएम गोल्डन टाइगर, चार हिम बाघों के आमने-सामने बैठे, जो भाई थे और जिन्हें सर्कस से बचाया गया था, जहाँ उन्हें करतब दिखाने के लिए मजबूर किया गया था, संफेद शेर और हिम तेंदुए के साथ बैठे। पीएम ने एक ओकापी को थपथपाया, खुले में चिम्पांजी से आमने-सामने हुए, जिन्हें एक ऐसी सुविधा से लाया गया था।

शब्द पहेली - 5798

1	2	3	4	5
6	7	8	9	
	10			
11	12	13	14	15
	16		18	
	17			20
21		23	24	
25	26	27		28
	29		30	

बाएँ से दाएँ

- पदमाकर, कमल सरोवर-5
- इस्लामी धर्म ग्रंथ-3
- देवस्थान, मंदिर-2
- शिव आवास-3
- उत्तम, मज्जन-2
- पति, शोहर-3
- दमकना-4
- टीस, पीड़ा-3
- झरने की आवाज-4
- अशा, इच्छा-2
- संध्या, शाम-2
- निराकार, भगवान-4
- बुझाना, शांति-3
- अभिप्राय-4
- आंचल-3
- घोड़ागाड़ी-2
- उष्ण-3
- पिता के पिता-2
- पंक्ति-3
- तहजीबदार-5

ऊपर से नीचे

- कथा कहने वाला-5
- चित, जी-2
- कार्यशाला, यंत्रालय-4
- माहिर, दक्ष-3
- आकाश, गगन-2
- कारावास-2
- योग्य-3
- अनुमान, अंदाज-3
- झगड़ा, कहासुनी-4
- मुगल सम्राट जहांगीर का एक नाम-3
- पक्षियों का शोर-4
- राहत, विश्राम-3
- मुसीबत, आफत-3
- होशियार, चेतावनी-5
- नगर-3
- संजीव कुमार

व लीना चंद्राकरर अभिनीत फिल्म

- मगरमच्छ-3
- दर, मूल्य-2
- भूमि, धरती-2
- पिता के पिता-2

शब्द पहेली - 5797 का हल

ब	े	ि	क	ल	व	ह	ख	न	स
इ	ग	न	त	र	क	स			
म			क	त					
न	क	ब	ज	न	श	र	ज	क	क्ष
अ	ल	स	ब	ह	क	न	प	र	य
य			स	ल	ि	न			स
श	र	न	त	र	क	स	ल	म	ग
ब	ह	न	त	र	क	स	ल	म	ग
स	न	त	र	क	स	ल	म	ग	ह

सूडोकु नवताल 5808

9			4		7
			7	9	
8					
4	5	8			
3		1			2
			9	7	6
					4
2		3	5		8

सूडोकु नवताल 5807 का हल

7	8	5	2	6	3	1	4	9
4	3	1	9	7	5	8	2	6
2	6	9	1	4	8	7	5	3
3	1	4	6	8	9	5	7	2
9	5	8	7	2	4	6	3	1
6	7	2	5	3	1	9	8	4
5	2	7	3	9	6	4	1	8
1	4	6	8	5	2	3	9	7
8	9	3	4	1	7	2	6	5

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भर जाने आवश्यक हैं।
प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
पहेली का केवल एक ही हल है।

शराब की कीमतें प्रति बोतल

नाम	छग	एमपी	महाराष्ट्र	दिल्ली	हरियाणा
आरएस	900	750	800	500	500
आरसी	900	500	700	500	550
रेड लेबल	2200	1800	2000	1500	1500
सिगनेचर	1200	1100	1000	800	900
टीचर्स	2000	1700	1900	1400	1300
ब्लैंडर	1200	1000	1000	750	800

नोट- छग में एस्ट्रा ड्यूटी को खत्म करने के बाद होने वाले संभावित रेट का उल्लेख किया गया है

हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित समाचार ही नहीं, विचार भी



छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए की शराब प्रतिवर्ष खपाई जा रही

एक्सट्रा ड्यूटी खत्म होगी, फिर भी दिल्ली, हरियाणा, मप्र से छग में शराब सबसे ज्यादा महंगी रहेगी, ऐसे में कैसे रुकेगी तस्करी

मिलाई-आलोक तिवारी/ राजनांदगांव-सचिन अग्रहरी

राज्य शासन द्वारा नई आबकारी नीति को मंजूरी देने के साथ ही विदेशी शराब पर लगने वाली करीब साढ़े नौ फीसदी की एक्सट्रा ड्यूटी को समाप्त करने का ऐलान किया गया है। इस घोषणा से छत्तीसगढ़ में शराब के दाम जरूर कम हो जाएंगे लेकिन प्रदेश में व्यापक पैमाने पर जारी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, दिल्ली और पंजाब से शराब की अवैध तस्करी पर शेष पेज 6 पर



ठेकेदार दे रहे 40 फीसदी कमीशन

प्रदेश के मुकाबले महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में शराब की बोलत की कीमत पहले से ही काफी कम है। इसके बाद भी उन प्रदेशों के शराब ठेकेदार तस्करी को करीब 40 फीसदी तक कमीशन भी दे रहे हैं। यही कारण है शेष पेज 6 पर

कार्रवाई के लिए अगला भी नहीं

प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा जिलों की सीमाओं के जरिए पड़ोसी राज्यों से शराब की अवैध तस्करी की जाती है। कई दफा तस्करी को पकड़ा भी जाता है लेकिन अधिकांश मामलों में तस्करी महकमे से बचकर सजाई करने में सफल शेष पेज 6 पर

कम नहीं होगा देशी शराब का रेट?

नई आबकारी नीति के मुताबिक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के मदिरा कय की दर पर 9.5% राशि के बराबर होता है, इससे खत्म किया जा रहा है। इससे अंग्रेजी शराब जो मीडियम रेंज और हाई रेंज की हैं, उनके दाम कम होंगे। चीप शराब जैसे गेला या इससे निचली स्तर की शराब की कीमतों में भी कमी की तयारी की गई है। शेष पेज 6 पर

हाई रेंज की शराब की सबसे ज्यादा कालाबाजारी

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाई रेंज की शराब की सबसे ज्यादा कालाबाजारी होती है। एमपी और महाराष्ट्र के रास्ते से शराब छत्तीसगढ़ पहुंचती है। प्रदेश में मीडियम रेंज में मेगडॉवल नंबर-1, बीपी, आईबी, आरएस, आरसी, सिगनेचर की ज्यादा खबर है। हाई रेंज में लोग 100 पाइपर, रेड लेबल, ब्लैक ड्रॉग, ब्लैक एंड वाइट पसंद करते हैं। गोवा जहां इस समय 520 रुपए बोतल के हिसाब से बिक रही है। वहीं नंबर-1, बीपी, आईबी 840 रुपए में मिल रही। आरएस, आरसी, सिगनेचर, ब्लैंडर स्प्राइट शेष पेज 6 पर

inh

छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल देखें

TATA PLAY airtel

चैनल नं. 1155 चैनल नं. 366

खबर संक्षेप

देशभर से दो महीनों में 61 भगोड़े गिरफ्तार

नई दिल्ली। पुलिस ने इस साल के पहले दो महीनों में देशभर से 61 भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। इनमें हत्या सहित अन्य अपराधों में संलिप्त व्यक्ति शामिल हैं। किसी व्यक्ति को भगोड़ा तब घोषित किया जाता है, जब वह जांच के चरण में या सुनवाई के दौरान कानून की प्रक्रिया से बचता है।

राइफल से गोली लगने से जवान की मौत

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के कमालकोट सेक्टर में सेना के एक जवान की सर्विस राइफल से गोली लगने से मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जवान की पहचान आंध्र प्रदेश के रहने वाले नायक भी टी राव (25) के रूप में हुई है।

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 42.35 लाख की ठगी

ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक पैथोलॉजी लैब के मालिक के साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर कथित तौर पर 42.35 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। एक जालसाज ने बदलापुर क्षेत्र के बेलावाली निवासी पीडित से फोन पर संपर्क किया। उसे शेयरों में निवेश करने का झांसा देकर आकर्षक लाभ का वादा किया।

टायर फटने से बेकाबू हुई कार, दो की मौत

लखनऊ। लखनऊ के हसनगंज इलाके में बुधवार को टायर फटने से बेकाबू हुई कार की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। दो अन्य घायल हो गए। यह घटना हसनगंज थाना क्षेत्र के नदवा रोड पर रात करीब एक बजे हुई जब तेज गति से जा रही एक कार टायर फटने से अनियंत्रित हो गई। उसने डिवाइडर पर सो रहे चार लोगों को कुचल दिया।

गांव से हेरोइन बरामद तस्करी की तलाश

चंडीगढ़। पंजाब के अमृतसर के जंडियाला के देवीदासपुर गांव से पुलिस ने 23 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। मादक पदार्थ की इस खेप का संबंध अमेरिका के एक तस्करी कार्रवाई के नेटवर्क से है। यह खेप अमेरिका में मौजूद तस्करी जसमीत सिंह उर्फ लक्की द्वारा संचालित तस्करी नेटवर्क से जुड़ी हुई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान

भारत और चीन के खिलाफ 2 अप्रैल से अमेरिका लागू करेगा जवाबी शुल्क

एजेसी ►► न्यूयॉर्क/वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन सहित अन्य देशों द्वारा उच्च शुल्क लगाए जाने की आलोचना की और इसे 'बेहद अनुचित' करार दिया। ट्रंप ने साथ ही घोषणा की कि अगले महीने से जवाबी शुल्क लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति ने जवाबी शुल्क को लेकर अपना पक्ष रखा और कहा कि ये दो अप्रैल से लागू जाएंगे। वह अन्य देशों से आयात पर वही शुल्क लगाना चाहते हैं, जो वे देश अमेरिका से होने वाले निर्यात पर लगाते हैं। ट्रंप ने मंगलवार रात कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, अन्य देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ शुल्क लगाए हैं और अब हमारी बारी है कि हम उन देशों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करें। यूरोपीय संघ (ईयू), चीन, ब्राजील, भारत, मेक्सिको और कनाडा क्या आपने उनके बारे में सुना है। ऐसे अनेक देश हैं जो हमारी तुलना में हमसे बहुत अधिक शुल्क वसूलते हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। 'व्हाइट हाउस' (अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) शेष पेज 6 पर

टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मार्च को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने साफतौर पर कहा कि जो देश हम पर जितना टैरिफ लगाएगा, हम उसपर उतना टैरिफ लगाएंगे। इस दौरान ट्रंप ने भारत और चीन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत हम पर 100 प्रतिशत आंटे टैरिफ लगाता है। भारत समेत चीन, मेक्सिको और कनाडा समेत कई देशों पर टैरिफ लगाएंगे।

ट्रंप ने क्यों चुनी 2 अप्रैल की तारीख?

सवाल ये है कि ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए 2 अप्रैल का ही दिन क्यों चुना? इसका जवाब खुद ट्रंप ने ही दिया। उन्होंने कहा कि वह 1 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लगाना चाहते थे, लेकिन "अप्रैल फूल डे" का आरोप नहीं लगाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील और भारत जैसे देश अमेरिका पर अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ से कहीं ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। उन्होंने इस स्थिति को अनुचित बताया। ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो देश अपने उत्पाद अमेरिका में नहीं बनाते हैं, उन्हें टैरिफ देना होगा और कुछ मामलों में तो हम बड़ी मात्रा में टैरिफ लगाएंगे।

चीन, मेक्सिको और कनाडा समेत कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान

खस बात



ऐसे समझें, कितना फायदा-कितना नुकसान

अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर भारत से कार मंगाता है तो 10 लाख कीमत वाली कार के लिए उसे आयात शुल्क के साथ करीब 12 लाख 50 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर भारत का कोई शख्स अमेरिकी कार खरीदता है तो उसे ज्यादा आयात शुल्क की वजह से 20 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। यह कीमतें इन उत्पादों की पहुंचने की कीमत (डिलीवरी फॉर) को जोड़ दीं हैं।

रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है

रेसिप्रोकल टैरिफ यानी परस्पर और जवाबी टैरिफ को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर टैरिफ, जिन्हें आयात शुल्क भी कहा जाता है, वह क्या होते हैं? आसान भाषा में समझें तो टैरिफ वह शुल्क होता है, जो कोई देश किसी अन्य देश से आयात होने वाले सामान पर लगाता है।

- आयात शुल्क घटने के बाद भारत में अमेरिकी उत्पादों की कीमतें कम हो जाएंगी। हालांकि, इससे रुपया कमजोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी मांग कम हो जाएगी। इसी तरह मांग बढ़ने की वजह से डॉलर और मजबूत होता जाएगा।
- अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क घटता है तो भारतीय आयकर के दायरे से बची हुई रकम को सस्ते होने वाले अमेरिकी उत्पादों पर खर्च कर सकते हैं।
- भारतीयों का धन अमेरिकी व्यापारियों को फायदा पहुंचाएगा और अमेरिकी जीडीपी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी।
- घरेलू उत्पादों की मांग कम होने से देश की जीडीपी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
- आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कम दर से उपभोक्ता अमेरिकी उत्पादों में ज्यादा रुचि दिखा सकते हैं।

49 किसानों की याचिका पर केंद्र-राज्य से मांगा जवाब



- गारे कोल ब्लॉक भू अधिग्रहण मामला
- प्रभावित किसानों की याचिका पर हुई सुनवाई

हरिभूमि न्यूज ►► बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गारे फोर बाई सिक्स कोल ब्लॉक भू अधिग्रहण से प्रभावित 49 किसानों की याचिका पर राज्य सरकार, कलेक्टर रायगढ़, एसडीओ घरघोड़ा और जिला स्टील एंड पावर लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में किसानों ने नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाए जाने के बावजूद छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 247 के तहत किए जा रहे भूमि अधिग्रहण शेष पेज 6 पर

भू अधिग्रहण की कार्रवाई असंवैधानिक

याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह भी बताया गया कि नया भूमि अधिग्रहण कानून पुनर्विचार और प्रभावित व्यक्तियों को कानूनी अधिकार देता है। इस नए भू अधिग्रहण कानून के आने के पश्चात भू राजस्व संहिता की धारा 247 में राज्य की विधानसभा ने केवल मुआवजे के संबंध में नए कानून लागू होने का संशोधन किया परंतु पुनर्विचार और पुनर्स्थापना के आदि पर कोई भी संशोधन नहीं है। शेष पेज 6 पर

प्रति एकड़ भूमि मुआवजे को भी चुनौती

याचिका में 2010 की राज्य सरकार की उस अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है जिसके द्वारा किसानों को प्रति एकड़ भूमि मुआवजे का निर्धारण आज 15 साल बाद भी किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से मध्यविकता प्रकृल भारत ने छुड़ाव को इस मसले पर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि पूर्व में एक शेष पेज 6 पर

संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन

चंडीगढ़ बार्डर सील, हिरासत में 100 से अधिक किसान



एजेसी ►► चंडीगढ़

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बैनर तले विभिन्न भागों को लेकर बुधवार से शुरू हुए सप्ताह भर के धरने के लिए चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रोक दिया। पंजाब भर में जगह-जगह कई अवरोधक लगाकर केंद्र शासित प्रदेश के सभी प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने मोहाली में रोपड़ से आए 100 किसानों को हिरासत में भी ले लिया है। इसके अलावा पुलिस ने पिंडू संघर्ष कमेटी के मंत्री को हिरासत में लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा 30 से अधिक किसान संगठनों का एक समूह है और उसने अपनी विभिन्न भागों के समर्थन में पांच मार्च से चंडीगढ़ में एक सप्ताह तक धरना देने का आह्वान किया है। पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक एच. एस. भुल्लर ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को किसी भी कीमत पर चंडीगढ़ पहुंचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों से बुधवार सुबह चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए किसानों को पंजाब पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर रोक दिया।

हर वाहन की जांच

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चौकी पर 100 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। किसानों को चंडीगढ़ जाने से रोकने के लिए हर वाहन की जांच की जा रही है। सगस्टर में पुलिस ने घरवाहन और भवानीगढ़ सहित कई स्थानों पर नाके लगाए। खरड में मागो माजरा टोल भवानीगढ़ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर अवरोधक लगा दिए।

क्या है मांग

एसकेएम ने अब निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 के आंदोलन का नेतृत्व किया था। वह कृषि विप्लव पर राष्ट्रीय नीति रूपांतरण के केंद्र के मंत्री के वापस लेने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी राज्य की कृषि नीति को लागू करने और राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर छह फसलों की मांग कर रहा है।

गुरुदर्शन मेले में सीएम साय



रायपुर। बाबा गुरु बासीदास की जन्मस्थली और कर्मस्थली गिरीदुपुरी में गुरुदर्शन मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वयं गुरु गद्दी का दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं सुखहाली की प्रार्थना की। 04 से 06 मार्च तक चलने वाले इस मेले में छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत से हजारों श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

- मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं और सुरक्षा का विस्तार
- मुख्यमंत्री की घोषणा पर मेले के आयोजन के लिए मिलेगी 50 लाख रुपए की राशि
- मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थायी शोड का होगा निर्माण



केदारनाथ और हेमकुंड साहिबजी रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी

केदारनाथ का सफर 9 घंटे के बजाय 36 मिनट में होगा पूरा!

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय रोप-वे विकास कार्यक्रम-पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोप-वे परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है। इससे केदारनाथ पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही एक अन्य परियोजना हेमकुंड रोप-वे के लिए भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। जिस दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लगता था, वहीं इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद सिर्फ 36 मिनट का समय लगेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को उत्तराखंड में दो रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।



हेमकुंड साहिबजी की कठिन यात्रा

वर्तमान में हेमकुंड साहिबजी की यात्रा गोविंदघाट से 21 किमी की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है। इसे पैदल या टट्टुओं या पालकियों द्वारा पूरा किया जाता है। प्रस्तावित रोपवे की योजना हेमकुंड साहिबजी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों और फूलों की घाटी में आने वाले पर्यटकों की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है, और यह (रोपवे) गोविंदघाट तथा हेमकुंड साहिब जी के बीच सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा।

पिछले साल आए ये 23 लाख श्रद्धालु

मंत्री ने कहा कि पिछले साल 23 लाख तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ साहिब का दौरा किया। रोपवे परियोजना के साथ यह संख्या बढ़कर 36 लाख होने की उम्मीद है। वैष्णव ने बताया कि पिछले साल 1.77 लाख लोग हेमकुंड साहिबजी पहुंचे और रोपवे से वहां जाने वाले लोगों की संख्या 10 गुना तक बढ़ने की उम्मीद है।

आस्था का मान भी, श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान भी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एसएस पोस्ट में लिखा, आस्थापूर्ण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके कुशल नेतृत्व में सोनप्रयाग से बाबा केदारनाथ धाम तक 12.9 किलोमीटर एवं गोविंदघाट से गुरु गोबिंद सिंह जी की तपोभूमि हेमकुंड साहिब की दो नए रोपवे परियोजनाओं की स्वीकृति से तीर्थयात्री सुगमता से बाबा केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन कर पाएंगे। यह परियोजनाएं तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी।



चिंतन

श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी 70% तक बढ़े

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह में भारत के श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी पर विश्वसनीय महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि विकसित भारत के लिए 2047 तक कार्यबल में 70 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। दरअसल, उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) ने सेवा क्षेत्र में महिलाओं पर समेकित आयोजित किया है, जिसमें केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने श्रमबल में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने की बात कही है। देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी की काफी संभावनाएं हैं। महिला उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए उद्यम पूंजी सहायता बढ़ाने के उपाय भी जरूरी हैं। श्रमबल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा, कौशल शिक्षा, उद्यम के लिए अवसर आदि क्षेत्र में काम करने होंगे। महिला श्रमबल को उत्पन्न शिक्षा के साथ सेक्टर उन्मुख स्किल प्रशिक्षण देना होगा, जो उद्यमी बनना चाहती हैं, उन्हें पूंजी से लेकर बाजार तक के माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता है। महिला उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी सहायता बहुत आवश्यक है। महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं के लिए मार्गदर्शन दिया जाना भी जरूरी है। सेवा क्षेत्र में महिलाओं के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जिसमें ऐसे पूर्वाग्रह हो सकते हैं जो उन्हें कार्यबल में प्रवेश करने से रोकते हैं। नेतृत्व की भूमिकाओं में भी वेतन असमानताएं हैं, नौकरी की सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं और घरेलू व पेशेवर जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। लगभग 45 प्रतिशत महिलाएं बच्चों की देखभाल और घरेलू प्रतिबद्धताओं को कार्यबल में भाग न लेने का कारण बताती हैं। लेकिन पिछले छह साल में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। शिक्षित महिलाओं के कार्यबल में शामिल होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और वेतन असमानता को लेकर कुछ चुनौतियों के बावजूद उनकी आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आज हम महिलाओं को सेवा क्षेत्र, प्रौद्योगिकी, वित्त और विनिर्माण क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देखते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले छह वर्षों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए 2017-18 में 22 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 40.3 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह महिलाओं के लिए श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में भी इस दौरान वृद्धि हुई है। महिलाओं के लिए श्रमबल भागीदारी दर 23 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 42 प्रतिशत हो गई है, पर जरूरत 70 फीसदी पर ले जाने की है। स्नातकोत्तर स्तर और उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त कुल महिलाओं में से 40 प्रतिशत 2023-24 में काम कर रही थीं, जबकि छह साल पहले यह आंकड़ा लगभग 35 प्रतिशत था। टेक सेक्टर में महिलाओं के लिए अनेक अवसर हैं। वास्तविक लैंगिक समानता के लिए प्रौद्योगिकी में समानता सुनिश्चित करने की तत्काल जरूरत है। महिला सशक्तिकरण की आधारशिला के रूप में डिजिटल समानता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दुनिया भर में 133 एआई प्रणालियों में से 44 फीसदी एआई प्रणालियां लिंग-समावेशी नहीं हैं। डिजिटल युग में उपयोक्ता व्यवहार, विशेषकर महिलाओं पर इसके प्रभाव का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर एआई पेशेवरों में केवल 22 फीसदी महिलाएं हैं, तथा नेतृत्व की भूमिकाओं में केवल 17 प्रतिशत महिलाएं हैं। विकसित भारत लक्ष्य के लिए शिक्षा के साथ श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी को उच्च स्तर पर लाया जाना चाहिए।

अर्थव्यवस्था
सतीश सिंह



शेयर बाजार में जल्द ही तेजी आने के आसार

अठ्ठाईस फरवरी को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के क्रैश करने के बाद भी शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। 3 मार्च को सेंसेक्स 112 अंक लुढ़का, जबकि निफ्टी 50.5 अंक। 4 मार्च को भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 5 मार्च को सुबह सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी देखी गई। चूंकि, सेंसेक्स में पिछले 5 महीनों से गिरावट दर्ज की जा रही है और निफ्टी में भी 1996 के बाद यानी 29 सालों के बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लिहाजा, छोटे निवेशकों में चक्रावट की स्थिति बनी हुई है। उनके मन में यह आशंका घर कर गई है कि शेयर बाजार में उनका पैसा सुरक्षित नहीं है और बाजार का बुरा दौर अभी जारी रहेगा। शेयर बाजार में देसी, विदेशी संस्थागत निवेशक, व्यक्तिगत विदेशी निवेशक आदि सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करते हैं। दोनों ही सूचकांक बेहद ही संवेदनशील हैं। जब सूचीबद्ध कंपनियों में से किसी खास कंपनी के शेयर की लगातार बिकवाली की जाती है तो उक्त कंपनी पर से निवेशकों का भरोसा कम हो जाता है और उस कंपनी के शेयरों की कीमत कम हो जाती है, जिससे निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है। शेयरों की कीमत में उतार-चढ़ाव आने के कई कारण होते हैं। जैसे, कंपनी का खराब वित्तीय प्रदर्शन या फिर कंपनी का किसी विवाद में पड़ना, राजनीतिक अस्थिरता, सरकार की नीतियां, डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना, वैश्विक अनिश्चितता, कारोबारी युद्ध की आशंका, भू-राजनैतिक संकट, अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा अपनाई गई नीतियां आदि। सबी शेयर बाजार का नियामक है, लेकिन सबी की उपस्थिति के बावजूद इसमें कृत्रिम रूप से गिरावट लाने और फिर उसे उठाने के कुछ मामले देखे गये हैं। ऐसा कुछ खास लोगों को फ्रायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिसमें सबसे अधिक नुकसान छोटे निवेशकों को होता है। बाजार में गड़बड़ी को भांपने के लिए सतर्क रहने और बाजार को समझने की जरूरत है। शेयर बाजार की चाल पर लगातार नजर रखकर संभावित नुकसान से बचा जा सकता है। यह जरूरी है कि शेयर बाजार में निवेश को जीवनयापन का जरिया बनाने की कोशिश नहीं की जाये और अत्यधिक लापरवाही से बचा जाये। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एक बड़ी राशि निवेश कर रखी है। 28 फरवरी को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 11,639 करोड़ रुपये की बिकवाली की, जबकि इस साल 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों ने की है। वहीं, घरेलू निवेशकों ने 28 फरवरी को लगभग 8 लाख 88 हजार करोड़ रुपये की बिकवाली की। इनके अलावा, शेयरों का अधिक मूल्यंकन होना और मनोवैज्ञानिक कारण भी शेयर बाजार के क्रैश के महत्वपूर्ण कारक हैं।

दरअसल, भारत में भेड़चाल की परंपरा है। कुछ लोगों को बिकवाली करते हुए देखने के बाद दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करने लगे। ऐसा इसलिए लग रहा है, क्योंकि 28 फरवरी को आईटी, टेलीकॉम, स्वास्थ्य, बैंकिंग, एफएमसीजी आदि सभी क्षेत्रों के शेयरों में बिकवाली दर्ज की गई है। इसलिए, बाजार के साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश प्रतीत नहीं हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई है, जो दूसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत (संशोधित अनुमान) रही थी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि विकास की रफ्तार में तेजी आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती करने से बैंकों को सस्ती दर पर पूंजी मिलेगी और वे सस्ती दर पर ऋण दे सकेंगे और जब सस्ती दर पर उधार मिलेगा तो आमजन और कारोबारी दोनों ऋण लेंगे, जिससे निवेश और बचत दोनों में तेजी आयेगी और खपत बढ़ेगी साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। वजट में सरकार ने साफ तौर पर बता दिया है कि उसका मकसद विकास को गति देना है। दिसंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर के 6.2 प्रतिशत रहने से विकास की गति में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी है। साथ ही, विकास दर में और भी इजाफा लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कटौती की है। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो शेयर बाजार में बिकवाली की गुंजाइश कम होगी और निवेशकों को अपने निवेश पर आकर्षक प्रतिफल मिलना संभव संकेत। इसलिए, निवेशकों को घबराने की कतई जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ बेवजह बिकवाली से बचने की आवश्यकता है।

(लेखक एसबीआईआई गौधीनगर में एसजीएम हैं। वे उनके अपने विचार हैं।)



विश्लेषण
अखिलेश आर्यन्दु

तमिलनाडु में हिन्दी विरोध वहां की राजनीति के खास मुद्दों में एक रहा है। यह विरोध आजादी के बाद से ही आंदोलन के रूप में लगातार चलता आया है। एक बार फिर हिंदी विरोध को राज्य की अवाग के हितों के खिलाफ बताकर राज्य सरकार आने वाले चुनाव में एक मुद्दे के रूप में देख रही है। जो नया विवाद हिंदी को लेकर राज्य सरकार पैदा कर रही है वह नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर है। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता में तमिलनाडु में कटौती का संकेत दिया है, जिसे तमिलनाडु सरकार ब्लैकमेलिंग के रूप में देख रही है। जाहिर तौर पर तमिलनाडु सरकार ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर राज्य के हित के खिलाफ हिंदी विरोध से सीधे-सीधे जोड़ दिया है। इससे लगातार विवाद बढ़ रहा है। वैश्वीकरण के युग में मातृभाषा के अलावा ज्यादा से ज्यादा भाषा सीखने की जरूरत बताई जाती है। फिर हिंदी भारत में अस्सी प्रतिशत से ज्यादा लोगों की भाषा है। ऐसे में तमिलनाडु के लोगों के लिए हिंदी सीखना कैसे उनके हितों पर कुठाराघात है। यह स्टालिन ने साफ नहीं किया है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने जिस तरह की हिंदी विरोध में टिप्पणी है उससे हिंदी को लेकर राज्य में नया विवाद खड़ा कर दिया है। स्टालिन का कहना है कि तमिलनाडु के विद्यालयों में तीसरी भाषा फार्मुल के तहत हिंदी थोपी नहीं जाएगी। उनकी हिंदी विरोधी इस टिप्पणी में कोई नई बात नहीं है। जाहिर तौर पर तमिलनाडु की राजनीति हिंदी विरोध को लेकर दशकों से चलती रही है। कभी-कभी तो हिंदी की खिलाफत करते-करते देश की खिलाफत भी हुई है। जिससे देशभर में तीखी प्रतिक्रियाएं भी हुई हैं लेकिन हिंदी विरोध तमिलनाडु की राजनीति में सबसे खास मुद्दों के रूप में राजनीतिक रत्न भूताने का कार्य करते रहे हैं। वहां चुनाव जीतने का यह सबसे वजनदार मुद्दा रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपना पर फेला रही है, जिसे स्टालिन अपने शासन के लिए चुनौती के रूप में देख रहे हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। केंद्रीय कार्यालयों में अंग्रेजी के साथ इसका प्रयोग अनिवार्य है। राज्य के स्कूलों में तमिल के साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल भाषा माध्यम के रूप में होता है लेकिन हिंदी का नहीं हो

हिन्दी विरोध के पीछे वोट बैंक की राजनीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीन भाषाओं की नीति है, जिसमें उस राज्य की भाषा, अंग्रेजी और एक अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है। हालांकि इस नीति में साफ तौर पर यह नहीं कहा गया है कि तीसरी भाषा हिंदी ही होनी चाहिए बल्कि यह कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है। इसके बावजूद, तमिलनाडु सरकार इसे एक तरह से हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में देख रही है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध वहां की राजनीति के तमाम खास मुद्दों में एक रहा है। यह विरोध आजादी के बाद से ही आंदोलन के रूप में लगातार चलता आया है। एक बार फिर हिंदी विरोध को राज्य की अवाग के हितों के खिलाफ बताकर राज्य सरकार आने वाले चुनाव में एक मुद्दे के रूप में देख रही है। जो नया विवाद हिंदी को लेकर राज्य सरकार पैदा कर रही है वह नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर है। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता में तमिलनाडु में कटौती का संकेत दिया है, जिसे तमिलनाडु सरकार ब्लैकमेलिंग के रूप में देख रही है। जाहिर तौर पर तमिलनाडु सरकार ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर राज्य के हित के खिलाफ हिंदी विरोध से सीधे-सीधे जोड़ दिया है। इससे लगातार विवाद बढ़ रहा है। वैश्वीकरण के युग में मातृभाषा के अलावा ज्यादा से ज्यादा भाषा सीखने की जरूरत बताई जाती है। फिर हिंदी भारत में अस्सी प्रतिशत से ज्यादा लोगों की भाषा है। ऐसे में तमिलनाडु के लोगों के लिए हिंदी सीखना कैसे उनके हितों पर कुठाराघात है। यह स्टालिन ने साफ नहीं किया है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने जिस तरह की हिंदी विरोध में टिप्पणी है उससे हिंदी को लेकर राज्य में नया विवाद खड़ा कर दिया है। स्टालिन का कहना है कि तमिलनाडु के विद्यालयों में तीसरी भाषा फार्मुल के तहत हिंदी थोपी नहीं जाएगी। उनकी हिंदी विरोधी इस टिप्पणी में कोई नई बात नहीं है। जाहिर तौर पर तमिलनाडु की राजनीति हिंदी विरोध को लेकर दशकों से चलती रही है। कभी-कभी तो हिंदी की खिलाफत करते-करते देश की खिलाफत भी हुई है। जिससे देशभर में तीखी प्रतिक्रियाएं भी हुई हैं लेकिन हिंदी विरोध तमिलनाडु की राजनीति में सबसे खास मुद्दों के रूप में राजनीतिक रत्न भूताने का कार्य करते रहे हैं। वहां चुनाव जीतने का यह सबसे वजनदार मुद्दा रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपना पर फेला रही है, जिसे स्टालिन अपने शासन के लिए चुनौती के रूप में देख रहे हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। केंद्रीय कार्यालयों में अंग्रेजी के साथ इसका प्रयोग अनिवार्य है। राज्य के स्कूलों में तमिल के साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल भाषा माध्यम के रूप में होता है लेकिन हिंदी का नहीं हो

सकता। स्टालिन हिंदी थोपने की बात केंद्र सरकार की भाषा नीति से असहमत या विरोध के रूप में चर्चा का विषय बनाना चाह रहे हैं। वे इसे इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे तमिलनाडु के बच्चों के साथ केंद्र सरकार बहुत बड़ा अनर्थ करने वाली है। स्टालिन यह भूल जाते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है। सभी राज्य अपनी आंचलिक भाषा को राज्य में लागू करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। राजीव गांधी सरकार ने तीन भाषा का जो केंद्रीय शिक्षा नीति का फार्मुला लागू किया था, वह तमिलनाडु में आज तक लागू नहीं किया गया। इसके बचाव में दुहाई यह दी जाती है कि इससे राज्य के बच्चों पर अनावश्यक मानसिक बोझ बढ़ेगा, जो उनके विकास में बाधा पैदा



करने का काम करेगा। राज्य सरकारों ने जनमानस को हिंदी विरोध के नाम पर राज्य में कई बार विकट हालात पैदा किये हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि बगैर सोचे-समझे प्रदेश की अवाग हिंदी के खिलाफ आंदोलन के साथ आ गया। धीरे-धीरे यहां के लोगों की मानसिकता यह बन गयी कि तमिलनाडु में हिंदी शिक्षा का माध्यम या हिंदी सीखना उनके विकास में रुकावट पैदा करती है, क्योंकि इससे तमिलों का अहित होगा।

तमिलनाडु सरकार यह भूल जाती है कि हिंदी ने किसी आंचलिक भाषा का इतने वर्षों में अहित नहीं किया बल्कि उसे विकास की धारा में अधिक प्रासंगिक बनाने का ही कार्य किया है। हिंदी देश के जितने भूभाग में बोली, समझी और लिखी जाती है वहां उससे हर किसी का विकास, प्रगति और हित ही हुआ है। हिंदी भाषा के रूप में हमेशा राष्ट्रीय एकता का सूत्रधार बनने का ही कार्य किया है। पूरे देश में जिस राज्य में वहां की प्रथम राजकीय भाषा नहीं है, वहां भी हिंदी ने एकता की माला में आंचलिक भाषा या बोली के साथ बड़ी बहन की तरह अपना कर्तव्य निभाने का कार्य किया है। ऐसे में तमिलनाडु में हिंदी वहां के आम आदमी और छात्रों के लिए बोझ या सिर दर्द कैसे बन जाएगी? इस सवाल का कोई तर्कसंगत जवाब तमिलनाडु

सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार हिंदी के स्वभाव, गुण, संस्कृति और सूत्रधार व बेहतर एकता निभाने के गुण को बगैर किसी तथ्य या तर्क से नकारती रही है, वही इस बार भी हो रहा है। राज्य सरकार हमेशा यह भूल करती आई है कि हिंदी राज्य में तीसरी भाषा के रूप में लागू होने से तमिलनाडुवासियों को उत्तर, पश्चिम और पूर्व भारत के लोगों से बेहतर संवाद करने में सुविधा हो जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो भाषा के नाम पर राज्य सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। इस तथ्य और सच को भला कौन नकार सकता है कि हिंदी ही सारे देश के लोगों को संवाद की भाषा के रूप में एक सूत्र में जोड़ सकती है, क्योंकि देश में इसके बोलने, लिखने और समझने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। हिंदी 'अनेकता में एकता' का सबसे बड़ी सूत्रधार है। तमिलनाडु के अलावा देश अन्य सभी भाषा भाषी लोग बहुत रुचि से हिंदी सीखते और बोलते हैं। पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल-हिंदी संगम जैसे आयोजनों का बड़ावा देकर हिंदी तमिल संस्कृति को मैत्री की माला में जोड़ने का कार्य किया किया। इससे हिंदी विरोध में कमी आई लेकिन स्टालिन ने मोदी के इस कोशिश को शुरू से ही पलौता लगाने का कार्य तो कभी, सनातन के खिलाफ टिप्पणी कर तो कभी हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोलकर सारे देश में कुचर्चित हुए। केंद्र सरकार चाहती है कि तमिल का आम आदमी उत्तर भारत के आम आदमी से भाषा-संस्कृति की एकता के सूत्र में बंधे। दोनों एक दूसरे की संस्कृति, साहित्य और कला को समझें और उत्तर भारत का व्यक्ति तमिल सीखकर तमिलनाडु की पुरातन संस्कृति और कला को समझे और अपनाए। मोदी की इस मैत्री वाली पहल से मुख्यमंत्री स्टालिन को क्या अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, इसलिए एक बार फिर आम लोगों को भड़काने के लिए जबर्न हिंदी थोपने जैसी भड़काऊ टिप्पणी करते फिर रहे हैं। स्टालिन का यह कहना भी कि तमिलनाडु हिंदी के हिंदी ने न जाने कितनी भाषाओं को निगल लिया है।

स्टालिन यह समझाने में असफल रहे हैं कि हिंदी से तमिलनाडुवासियों का किस तरह विकास अवरुद्ध होगा और अंग्रेजी के जरिए ही उनका विकास हो सकता है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और तमिल दो हैं, इससे क्या बच्चों पर अंग्रेजी सीखने की दोहरी मार नहीं होती। वोट बैंक के मद्देनजर या आने वाले वक्त में सत्ता छिनने के डर से यदि वह भाषाई विरोध की आग फिर धधकाई जा रही है तो इससे न तो तमिलवासियों को कोई हित होने वाला है, न उन बच्चों का जो हिंदी सीखकर उत्तर भारत में बेहतर नौकरी के अवसर को पा सकते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और हितक हैं। वे उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

स्वीकारोक्ति: गलतियों को खुले मन से स्वीकार करें



संकलित
दर्शन

कार्य संपन्न होने की प्रक्रिया में कदाचित् त्रुटियां रह सकती हैं, भले ही कार्य निष्ठा से किया जाए। अगर कोई आपके किए-कराए में चूक निकाले, उस पर टिप्पणी करे तो नाराज होने के बजाय उसे खुलेमन से स्वीकार करें। वैसे आप गलतियां करने से तभी बच पाएंगे, जब कुछ नहीं करेंगे। अपने अवगुण या खोट की स्वीकार करना श्रेष्ठ मानवीय गुण है। औसत सोच का व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ होता है। अवांछनीय या अनुचित कार्य की अनदेखी का अर्थ है संशोधन के द्वार बंद कर देना। सर्वगुणसंपन्न व्यक्ति तो साक्षात् देवता है। भूल-चूक की स्वीकारोक्ति प्रगति की राह में पहला चरण है। इस प्रक्रिया में आप अनेक व्यक्तियों का विश्वास जीतते हैं। जिस सत्य का सामना करने के लिए तैयार नहीं, उसे बदलेंगे कैसे? जिसे अपनी अपूर्णताओं का आभास नहीं वह मूर्ख नहीं, बल्कि दयनीय है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने अवगुणों को दूर नहीं कर सकेगा। जिस सीमा तक हम अपनी अपूर्णताओं और अवांछनीय व्यवहार के प्रति सजग रहेंगे और समाधान की ओर अग्रसर रहेंगे, उसी अनुपात में हम नैतिक रूप से समृद्ध होंगे। व्यावहारिक जीवन में संयमी, संयत व्यक्ति से भी भूल-चूक हो जाती है। उन्नत सोच का व्यक्ति अपनी भूल को तुरंत स्वीकार कर लेगा। मध्यम सोच वाले को गलती का अहसास तो होगा, वह मन में कुढ़ेगा भी, किंतु लज्जित होने की आशंका से वह गलती को खुलेआम नहीं मानेगा। अपनी कृति के प्रति अत्यंत चौकस अधिसंख्य व्यक्ति अपने गलत कार्य या कथन की वैसी संरक्षा करेंगे जैसे सद्गुण या शील दांव पर हो।



संकलित
प्रेरणा

सेहत और ज्ञान से जुड़े कामों में देर न करें

एक दिन श्रीकृष्ण उद्धव की भेंट हुई तो श्रीकृष्ण ने उद्धव को एक ब्राह्मण की कहानी सुनाई। श्रीकृष्ण ने बताया कि एक ब्राह्मण ने खेती और व्यापार करके खूब धन कमाया था। वह धनी था, वह बहुत ही कंजूस भी था। धन आया तो उसका मन गलत कामों में लग गया, वह लालची भी था। बुरी आदतों के साथ ही उसे अहंकार भी हो गया, बात-बात पर वह गुस्सा करने लगा। अपने मित्रों से और रिश्तेदारों ने ही छीन से व्यवहार नहीं करता था। ब्राह्मण के व्यवहार की वजह से उसके घर-परिवार के लोग और मित्र लोग दुखी रहने लगे। वह धनी था, लेकिन और धन कमाना चाहता था। कंजूस इतना था कि वह अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता था, लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे उसका धन खर्च होने लगा। कुछ धन उसके घर-परिवार वालों ने ही छीन लिया। कुछ चोरी हो गया। कुछ चीजें अपने आप नष्ट हो गईं। धनी ब्राह्मण का बुरा समय शुरू हुआ तो उसे व्यापार में भी नुकसान हो गया। इसी तरह कुछ ही दिनों में उसका पूरा धन बर्बाद हो गया। अब वह गरीब हो गया तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। गरीबी के दिनों में उस ब्राह्मण को अपनी गलतियों याद आने लगीं। वह सोचने लगा कि उसने कभी भी किसी पर धन खर्च नहीं किया। घर-परिवार के लोगों से और मित्रों से बुरा व्यवहार किया। अब मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने कभी भी अपने धन का सही उपयोग नहीं किया।

फाल्गुन महोत्सव



आगरा में बुधवार को श्री खाटू श्याम फाल्गुन महोत्सव के पहले दिन मठा रंगा और गुलाल के साथ जश्न मनाते हुए।

आज की पाटी

सेनेक्टर सिस्टम कर सकता है सपनों को पूरा

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 से 10वीं की परीक्षा पेटन में कुछ बदलाव करने जा रहा है। निःसंदेह हमारे शिक्षाविदों ने विद्यार्थियों के भले के लिए ही सुधारमूलक कदम उठाने की सिफारिश की होगी। हम हम अपने समय के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली की तुलना आज के समय से करते हैं तो अनुभव करते हैं कि विद्यार्थी विज्ञान और गणित जैसे अंडरस्टैंडिंग आधारित विषयों में पिछड़ रहे हैं। आज विद्यार्थियों की न तो इंग्लिश में पकड़ है और न ही हिंदी भाषा में। कई प्रदेशों में तो विद्यार्थी अपनी मातृ भाषा में भी पास नहीं हो रहे हैं। इसलिए बोर्ड परीक्षा के 'उच्च दस्त' को समाप्त करने के लिए दो बार परीक्षाओं का प्रावधान होगा, 'सर्वश्रेष्ठ दो प्रयासों में से सर्वश्रेष्ठ' के चुनाव की छूट भी होगी। - विवेक सोनी, गरियाबंद

करंट अफेयर

एआई डीपफेक लोगों की पहचान के लिए खतरा

आपकी आवाज की कीमत कितनी है? यह लगभग 100 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जितनी हो सकती है। हाल ही में एबीसी न्यूज वेरिफाई ने संघीय सीनेटर जैकी लैम्बी की आवाज की उनकी अनुमति लेकर क्लोनिंग की और इसपर इतनी ही राशि खर्च की और इसके लिए आसानी से सुलभ एक ऑनलाइन मंच का इस्तेमाल किया। यह उदाहरण यह रेखांकित करता है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ऐप्स, जो डीपफेक या वॉयस क्लोनिंग के रूप में किसी व्यक्ति की छवि और/या आवाज की कृत्रिम प्रतिकृति बनाते हैं, सस्ते और उपयोग में आसान होते जा रहे हैं। इससे न केवल लोकतंत्र की कार्यप्रणाली (विशेषकर चुनावों के समय) को गंभीर खतरा पैदा होता है, बल्कि व्यक्ति की पहचान को भी खतरा होता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी व्यक्ति की छवि या आवाज को उनकी अनुमति के बिना डिजिटल रूप से क्लोन किया जाता है तो उनकी पहचान के लिए कानून अर्पणित है। ऐसे में 'व्यक्तिगत अधिकार' स्थापित करने से मदद मिल सकती है। फर्जी की पहचान करना मुश्किल डीपफेक प्रौद्योगिकी ऐसी सामग्री तैयार करने में सक्षम है जो अति वास्तविक प्रतीत होती है।



विचार है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खाद्य मानकों में साबुत अनाज वाली ब्रेड को ऐसी ब्रेड के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें या तो पूर्ण अनाज होता है या फिर ऐसी ब्रेड जिसमें अनाज के सभी भाग मूल अनुपात में मौजूद होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खाद्य मानकों में इन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए निर्माता कानूनी तौर पर सफेद ब्रेड में थोड़ी मात्रा में साबुत अनाज मिला सकते हैं, ताकि उत्पाद अधिक स्वास्थ्यवर्धक लगे।

ऑफ बीट

साबुत अनाज व चोकरयुक्त आटे से बनी ब्रेड में क्या अंतर

यदि आप ब्रेड खरीदने के लिए दुकानों पर जाते हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार के विकल्प मिलेंगे। लेकिन बिक्री पर उपलब्ध सभी प्रकार के उत्पादों के बीच अंतर का पता लगाना कठिन हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के खाद्य मानकों के अनुसार, साबुत अनाज की ब्रेड मूल अनाज के सभी भागों (एंडोसर्म, रोगाणु और चोकर) से बने आटे से बनाई जाती है, जो उनके मूल अनुपात में होता है। चूंकि इसमें अनाज के सभी भाग शामिल होते हैं, इसलिए चोकरयुक्त आटे से बनी ब्रेड आमतौर पर सफेद ब्रेड की तुलना में गहरे रंग की और थोड़ी अधिक भुरी होती है, जो केवल एंडोसर्म का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। साबुत अनाज की ब्रेड के बारे में क्या

टैंड

गोसेवा से आत्मिक शांति

गोमता मे करोड़ों देवी-देवताओं का वास माना गया है। वे केवल हमारी आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और संवेदनाओं की आधारशिला भी हैं। उनकी सेवा से जो आत्मिक शांति, सुकृत और परमात्मिक की अनुभूति होती है, वह अप्रतिम है। -रेखा गुप्ता, सीएम, दिल्ली



कुलियों के अधिकार

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मगदूद के दौरान कुलियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। मैं इनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखूंगा और इनके अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ूंगा। -राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद



अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। जो सोचते हैं कि 'निलंबन' से सच की गुंजाबन पर कोई लागू लाग सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बयान है। -अखिलेश यादव, सपा सांसद



खान-पान पर दें ध्यान

हमें 'द लैस्ट एंड' के अध्ययन को गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी खान-पान की आदतों और शारीरिक गतिविधियों की दिशा में काम करना चाहिए, खास तौर पर युवा आबादी के बीच। -किरण मजुमदार-उठी, छात्री



हमारा पता

हरिभूमि कार्यालय

रिंग रोड नं. 2, गौरवपथ, बिलासपुर
फोन: 401050, 271016, फैक्स: 271018
ई-मेल: haribhoomibsp@gmail.com
वेब-साइट: www.haribhoomi.com

खून की कमी • पेडू में दर्द • कमर कटना • तनाव • चिड़चिड़ापन

90 वर्षों से महिलाओं की No.1 औषधि व टॉनिक

कमज़ोरी • हथेली व तलवों में जलन • खून साफ़ करे • रूप निखारे

आदि में सहायक

पूरे माह रहें एक्टिव, फिट व स्वस्थ

हेमपुष्पा

Helpline: 011-23261111

खबर संक्षेप

धमतरी और दुर्ग कलेक्टर बदले गए

रायपुर। राज्य शासन ने दो कलेक्टर सहित पांच आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। रायपुर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा को धमतरी का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं आईएएस अभिजीत सिंह को दुर्ग जिले के कलेक्टर नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। जिन आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला किया गया है, उनमें 2012 बैच के आईएएस अभिजीत सिंह को दुर्ग का कलेक्टर बनाया गया है, इससे पहले वह विशेष सचिव गृह एवं जेल विभाग और चिकित्सा विभाग सहित कई विभागों में अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे। 2018 बैच के आईएएस अविनाश मिश्रा को धमतरी का कलेक्टर बनाया गया है। वे रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त और रायपुर स्मार्ट सिटी में परस्थ थे। इसके अलावा साल 2019 बैच की आईएएस रेना जमीन, उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 2019 बैच के आईएएस ऑफिसर विश्वदीप को रायपुर नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें रायपुर स्मार्ट सिटी का प्रबंध संचालक भी नियुक्त किया गया है। 2020 बैच के आईएएस कुमार विश्वंजन को चिप्स का मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सीईओ जिला पंचायत रायपुर के पद पर परस्थ किया गया है।

सेक्वोरिटी सर्विसेस कंपनी ने रोका कर्मचारी का वेतन रायपुर।

आचार संहिता हटने के बाद कलेक्टोरेट में आम लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए स्थाई जनदर्शन कार्यक्रम फिर शुरू हो गया है। इस जनदर्शन में दो दिन पहले सेक्वोरिटी सर्विसेस कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी ने वेतन नहीं मिलने की शिकायत की थी। इस शिकायत पर संबंधित प्रकरण को श्रम विभाग को मार्क कर भेजा गया था, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए विभाग ने सेक्वोरिटी सर्विसेस कंपनी प्रबंधक से कर्मचारी को उसका रोका गया वेतन लगभग चार हजार रुपए दिलाने की कार्यवाही की। स्थायी जनदर्शन के नोडल अधिकारी मनोज पैकरा ने बताया कि सेक्वोरिटी सर्विसेस कंपनी में कार्य करने वाला लिंगराज साहू ने जनदर्शन में शिकायत की थी कि जिस कंपनी में वह कार्य करता है, उसके प्रबंधक ने उसका वेतन रोक दिया और और मांगने पर टालकर उसे लगातार घुमा रहा है। लिंगराज के इस शिकायत पर उन्होंने इस प्रकरण को श्रम विभाग को प्रेषित किया था, जिसके बाद विभाग के सहायक श्रमायुक्त आरके प्रधान ने इस मामले को तत्काल सज्ञात में लेते हुए संबंधित कंपनी के प्रबंधक को कार्यालय में बुलवाया और लिंगराज को रुका वेतन नहीं देने का कारण पूछा। इस पर प्रबंधक ने अपनी गलती मानते हुए लिंगराज को उसका रोका गया वेतन तत्काल दिया गया।

छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के प्रदेशाध्यक्ष का किया सम्मान रायपुर।

पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष महेश दर्यानी के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश कार्यालय में सिंधु साधु समाज के अध्यक्ष मुली उदसी का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही महासचिव बलराम आहजा का पुष्प गुच्छ, शॉल और श्रीफल से सम्मान किया। इसी दौरान अध्यक्ष श्री दर्यानी ने अपने कार्यकाल की विभिन्न उपलब्धियों से अवगत कराया। सम्मान करने वालों में राजा जेठानी, अमर चंदानी, गौरव मंथानी, रितेश वाधवा, अनिल लाहोरी, विनोद संतवाणी, आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

भाजपा विधायक ने कहा- पूर्ववर्ती सरकार में मुआवजे के भ्रष्टाचार का रैकेट चल रहा था

मंत्री ने कहा- पहली बार ऐसी जानकारी आई, इसकी जांच कराई जाएगी

हरिभूमि न्यूज: रायपुर।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सुशील शुक्ला ने सर्पदंश से हुई मौत के बाद मुआवजा देने को लेकर पूछा कि जशपुर को छत्तीसगढ़ का सर्पलोक कहा जाता है। जशपुर में 2022, 23, 24 में तीन साल में सर्पदंश से 96 मौतें हुई हैं, जबकि बिलासपुर में सर्पदंश से 431 मौतें हुई हैं।



बार ये जानकारी सामने आई है, इसकी जांच कराई जाएगी। विधायक ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार में शिकायत

वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोप पर चुन-चुन कर दिया जवाब, आपके थोथे नारों से जनता त्रस्त थी, अब ब्लेम गेम नहीं चलेगा

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पर सामान्य चर्चा में विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए जबरदस्त पटलवार किया। खास बात ये रही कि उन्होंने विपक्ष के नेता, सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोप का चुन-चुनकर जवाब दिया। श्री चौधरी ने कहा कि आपके थोथे वादों से जनता त्रस्त रही, अब ब्लेम गेम नहीं चलेगा। केवल राजनीति के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए। श्री चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर कहा जिसमें उन्होंने कहा था कि निगम की दस सीट जीतकर भाजपा ने रिकार्ड तोड़ा नहीं है। इसके जवाब में कहा कि वे भी दस में दस जीते थे, लेकिन स्थानीय चुनाव में दो वोट के अधिकार को छीनकर एक वोट कर दिया गया था। एक व्यक्ति को रायपुर का मेयर बनाने के लिए नगरीय इलेक्शन का सिस्टम बदला था। वह डायरेक्ट चुनाव जीत नहीं सकता था। वह पार्षद चुनाव भी हार गया। ये जनता के अधिकार की हत्या कर रिकार्ड बनाते हैं। ऐसी जीत उन्हें ही मुबारक। अब हमारी सरकार ने दो वोटों का अधिकार वापस दिया है। ये चुनाव जनमत संग्रह है। हमारी सरकार ने इसकी हिम्मत की। डायरेक्ट इलेक्शन अलग होता है, इनडायरेक्ट अलग होता है। दस में दस सीधे वोट देकर जनता ने हमारे प्रत्याशी जिताए, ये जनमत संग्रह है। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा मानव विकास के संबंध में कही गई

बजट पर सामान्य चर्चा का हुआ समापन, चौधरी बोले- राजनीति के लिए आलोचना नहीं

बात के जवाब में वित्त मंत्री ने आंकड़ों सहित बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इन्होंने कुल मिलाकर 5-7 हजार करोड़ रुपए बांटे वह भी चार किस्तों में। लेकिन हमारी सरकार ने पिछले साल में 13 हजार 30 करोड़ और इस साल 12 हजार करोड़ रुपए किसानों को एक साथ भुगतान किया। किसानों के धान के भुगतान, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान, दीनदयाल भूमिहीन योजना, गन्ना किसानों को बोनस और गन्ना की एमएसपी सहित सवा साल में किसानों को एक लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है।

यही कारण है कि जनता का हर चुनाव में हमें आशीर्वाद मिल रहा है। विपक्ष के सदस्य उमेश पटेल और राधवेंद्र कुमार सिंह के आरोप का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास दर 7.51 है जो देश के राष्ट्रीय औसत 6.7 से अधिक है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार ने एफआरबीएम एक्ट और आरबीआई की गाइड लाइन का अक्षरशः पालन किया है और जीएसटीपी का 19 प्रतिशत ही कर्ज लिया है। इसके जवाब में राधवेंद्र

सिंह ने कहा कि आपका ही डाटा 28-29 प्रतिशत बता रहा है, इससे कम है तो आंकड़े रख दें। श्री चौधरी ने ये भी कहा कि हमने 19 हजार करोड़ का अनुपूरक पिछली सरकार के गड़बड़ पाटने के लिए लाए थे।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत द्वारा गोल्फ कोर्स बनाए जाने पर ये कहा था कि इसकी जरूरत ही क्या है, यहां कौन गोल्फ खेलता है। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इनवायरमेंट बनाने के लिए ये किया गया है। जापान कोरिया के निवेशक वहां नहीं जाते जहां गोल्फकोर्स नहीं होता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उनकी सरकार के कार्यकाल में धान खरीदी पर केंद्र द्वारा अंडंगा लगाए जाने के आरोप पर वित्त मंत्री ने कहा कि यहां से केंद्र में 24 लाख मीट्रिक टन चावल पूर्व में लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 61 लाख मीट्रिक टन केंद्र ने किया। यह एक गैर भाजपा शासित राज्य से 93 लाख मीट्रिक टन धान के चावल लिए गए। अगर ये हुआ तो केंद्र सरकार की वजह से। बजट भाषण को हाथ से लिखे जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि हाथ से लिखना विशेष बात नहीं है जो इमोशन फील कर रहा था इसलिए लिखना चाहिए था। उन्होंने अंत में कहा कि केवल राजनीति के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए।

25 साल की उपलब्धियों पर अपनी पीठ थपथपा रहे- महंत

विधानसभा में बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरकार को इस बात के लिए आड़े हाथों लिया कि नए बजट में 25 साल की उपलब्धियों को शामिल कर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक साल में कौन सा संस्थान विकसित किया है एक का भी नाम बताएं। एक साल में आपने क्या किया है ये बताएं।

डॉ. महंत ने अपने भाषण की शुरुआत इस बात से की कि वित्त मंत्री आंकड़ों के जादूगर हैं, बाजीगर हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने वित्त मंत्री के लिए कहा कि आपने बजट भाषण में एक बात गलत कही कि पिछली सरकार ने लोकतंत्र के विश्वास की हत्या की। ये कहना आपतिजनक है। आपको ये कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि आपने एक साल में क्या विकसित किया है। एक बड़े संस्थान का नाम बताएं जिसकी नींव रखी गई है। नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा कि आपने बजट में 25 साल का उल्लेख कर

अपनी पीठ थपथपाई है। उन्होंने सरकार के पिछले बजट के दौरान पेश किए गए इलेगन ज्ञान(जीवायुएन) की बात करते हुए कहा कि आप गरीब किसे मानते हैं। उनके लिए क्या किया। सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि इसी सर्वे में बताया गया है कि वर्ष 2025 में कुल 6 पीए आवास बने हैं। यही नहीं 17 लाख बेरोजगारों के भत्ता देना बंद कर दिया। 33 हजार शिक्षकों की भर्ती करने की बात कही थी। लेकिन नहीं किया। राज्य के पांच शक्कर कारखाने बंद हो गए हैं। वहां शक्कर गुड़ नहीं बनी रहा है, राब से शराब बन रही है। अपराध की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि 2024 में बलात्कार के 3191 मामले सामने आए हैं। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा में सबसे ज्यादा मामले हैं। राज्य में हर तीन घंटे में एक महिला से रेप हो रहा है। सुशासन अभिसरण मुख्यमंत्री का विभाग है, लेकिन इसका काम दो एनजीओ से करवा रहे हैं। क्या राज्य में इस काम के लिए अधिकारी नहीं हैं।

भूपेश ने हस्तलिखित बजट में निकाली खामियां

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए हस्तलिखित बजट भाषण के संबंध में कहा कि यह सौ पेज की एक रफ कॉपी है। क्या वित्त मंत्री को अपने सचिवालय पर भरोसा नहीं है। बजट एक दस्तावेज है जो हमेशा रहेगा, लेकिन बजट भाषण में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह हास्यास्पद है। पेज 97 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी में लिख रहे हैं। वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में कहा गया कि हमने 10 में से 10 बिगम जीतकर रिकार्ड तोड़ा है। इस पर श्री बघेल ने कहा कि रिकार्ड बनाया है, तोड़ा नहीं है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने भी दस सीटें जीती थीं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार 25 साल की उपलब्धियों को आप आपने खते में कर रहे हैं। पीएम आवास योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 18 लाख आवास की योजना बनी थी। सर्वे हुआ था तब भी 7 लाख आवास हमने बनाए, आपने 11 लाख। अब तक 13 हजार लोगों ने ही गुड प्रवेश किया है।

हुई है। सर्पलोक जशपुर में 96 मौतें होती हैं और बिलासपुर में 400 से ऊपर मौतें सांप काटने से बताई जा रही है। राजस्व के अधिकारी सीएमओ से पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की जानकारी मांगते हैं और सीएमओ उस रिपोर्ट के बिना डॉक्टर के प्रतिवेदन को सत्यापित करते हैं। राजस्व और स्वास्थ्य अधिकारी की मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला हुआ है। क्या इसकी सचिव स्तर के अधिकारी से जांच कराएंगे? मंत्री टंकुराम वर्मा ने कहा, मुआवजे की प्रक्रिया ही यही है। जैसे सर्पदंश से कोई पीड़ित हॉस्पिटल गया और उसकी मौत हो गई, तो स्वास्थ्य विभाग से मिले प्रमाणपत्र के आधार पर राजस्व विभाग उन्हें मुआवजा देते हैं। अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। विधायक के पास यदि ऐसी कोई शिकायत है, तो इसके बारे में बताएं, इसकी जांच और कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने कहा कि कलेक्टर और एसडीएम द्वारा मुआवजा देने की बात है, क्या इसकी सचिव स्तर के अफसर से जांच कराई जाएगी।

सर्पदंश पर कैसे मिलेगा मुआवजा- धरमजीत

भाजपा विधायक धरमजीत सिंह ने पूछा कि दूरस्थ किसी क्षेत्र में यदि किसी को सांप काट लेता है, तो इसके लिए क्या-क्या करना पड़ता है। इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। मंत्री टंकुराम वर्मा ने कहा, सर्पदंश और इसके इलाज के लिए वैक्सिन सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध रहता है। किसी को यदि सांप काटता है, तो तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। समय पर अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो इलाज हो जाता है। यदि समय पर नहीं पहुंच पाए, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमाणपत्र के बाद एसडीएम या कलेक्टर की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। विधायक धरमजीत सिंह ने कहा, सांप काटने के बाद क्या-क्या प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। मंत्री ने जवाब दिया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ये बात आएगी कि सर्पदंश से मौत हुई है। इसके बाद प्रमाणपत्र बनेगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सभी लोगों का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं- कौशिक

विधायक भावना बोहरा ने पूछा कि सर्पदंश के बाद एंटी वेनम सिर्फ जिला चिकित्सालय में है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी वेनम नहीं है, जिससे समय पर इलाज नहीं हो पाता। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने जवाब दिया कि सभी अस्पतालों में एंटी वेनम है। धरमलाल कौशिक ने कहा, पूरे छत्तीसगढ़ में नाग लोग जशपुर है, लेकिन हैरानी हो रही है कि बिलासपुर में 400 से ज्यादा लोगों की सर्पदंश से मौतें हो रही हैं। पहचान बदल रही है। सवाल है कि सारे लोगों को पोस्टमॉर्टम हुआ है या नहीं। यदि पोस्टमॉर्टम नहीं हुआ है, तो उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी का कारनामा, अपनी पत्नी के नाम पर निकाल लिया सरकारी पैसा

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद में केज कल्चर अनुदान राशि में अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने अनुदान की पात्रता शर्तों और भौतिक सत्यापन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, बालोद जिले में एक अधिकारी की पत्नी के नाम पर 19 लाख रुपए जारी हुआ है। स्वीकृत अनुदान राशि में अनियमितता की गई है। उन्होंने पूछा कि आपके

पास बिना भौतिक सत्यापन के राशि जारी करने का कोई मामला आया है क्या? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। कांग्रेस विधायक ने कहा, जिले का एक अधिकारी ने अपनी पत्नी के नाम पर केज कल्चर की राशि निकाली है। उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग की। मंत्री जायसवाल ने कहा, इस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

मामले में कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि इस मामले में शासन को शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। सहायक संचालक आरके बंजारे को अब रिटायर होने के बाद आरोप पत्र जारी किया गया है। 3 करोड़ से अधिक की अनियमितता का यह मामला है। उन्होंने कहा, मामले में जांच करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अलग-अलग परिवार व लोगों के लिए काम किया गया।

फिट से तो बनते हैं...

बिज़नेस का लोन मंजूर

नई मशीनें लाओ

जल्दतर जितना ही लोब लो

समय से किश्त चुकाओ

नई कार

शॉपिंग

हॉलिडे

बिज़नेस का लोन मंजूर

जिम्मेदारी से लोन लें, अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखें।

समझदार बनें, वित्तीय अनुशासन का पालन करें।

आरबीआई कहता है...

वित्तीय समझदारी, समृद्ध नारी

अधिक जानकारी के लिए,
www.rbi.org.in पर विजिट करें
फीडबैक देने के लिए,
rbikehtrahai@rbi.org.in को लिखें

जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

वह दिन दूर नहीं जब भारत 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा : पीएम मोदी

एजेंसी नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने सभी हितधारकों से रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास और नवोन्मेषण में निवेश करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करना जरूरी है। बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार में मोदी ने कहा कि सरकार ने 2014 से तीन करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उन्नत करने और पांच उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का फैसला भी किया गया है।

अर्थव्यवस्था एक दशक में 66 फीसदी बढ़ी

प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक दशक (2015-2025) में 66 प्रतिशत बढ़ी है। भारत वर्तमान में 3,800 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती



प्रमुख अर्थव्यवस्था है और वह दिन दूर नहीं, जब देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा।

शिक्षा व शोध के लिए 500 करोड़ आवंटित

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के बराबर कौशल विकास को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि एआई से अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ रुपये का योगदान मिल सकता है। 'इस दिशा में, हमने बजट में एआई आधारित शिक्षा और शोध के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।'

पर्यटन युवाओं को रोजगार देने में सक्षम

मोदी ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत तक योगदान करने और करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार देने की क्षमता है। उन्होंने कहा, 'पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश में 50 नवत्यों का विकास किया जाएगा।'

शहरी चुनौती कोष के लिए एक लाख करोड़

पीएम ने कहा कि इन नवत्यों में होटलों को बुनियादी ढांचे का ढांचा देने से पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध शहरीकरण जरूरी है। हमने शहरी चुनौती कोष के लिए एक लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है।'

10 हजार अतिरिक्त मेडिकल सीट की घोषणा

इस साल के बजट में, हमने 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीट की घोषणा की है। अगले पांच साल में चिकित्सा क्षेत्र में 75,000 और सीट जोड़ने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का ढांचा देने के सरकार के फैसले के बारे में भी बात की और कहा कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इकाटी अगले साल भारत में आएगी मोटोकॉस बाइक

एजेंसी नई दिल्ली

इटली की सुपरबाइक विनिर्माता इकाटी की भारतीय बाजार में अपना पार्टफेलियो बढ़ाने के लिए अगले साल अपनी मोटोकॉस बाइक को उतारने की योजना है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मोटोकॉस बाइक मुख्य रूप से खराब रास्तों से होकर गुजरने वाली हल्के वजन की मोटरसाइकिल होती है। इनका इस्तेमाल खराब रास्तों से होकर गुजरने वाली प्रतियोगिता में किया जाता है। इकाटी की भारतीय बाजार के लिए मौजूदा उत्पादों के उन्नत संस्करणों के अलावा कई नए उत्पादों को पेश करने की तैयारी है। इकाटी इंडिया के प्रबंध निदेशक विपुल चंद्रा ने कहा कि कंपनी स्कैम्बलर, मल्टीस्ट्रूडा के अलावा अन्य मॉडल के नए संस्करणों को आने वाले समय में पेश करेगी। चंद्रा ने कहा, वर्ष 2026 में हम देखेंगे कि कंपनी मोटोकॉस बाइक भी भारत में लेकर आएगी। हमने पहले ही वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेना शुरू कर दिया है।

नई वोल्वो एक्ससी90 भारत में 1.03 करोड़ रुपए में हुई लांच



नई दिल्ली। लम्बरी कार और एसयूवी बनाने वाली पॉपुलर स्वीडिश कंपनी वोल्वो ने भारतीय बाजार में अपनी नई एक्ससी90 एसयूवी लांच कर दी है और इसकी शुरुआती कीमत करीब 1.03 करोड़ रुपए है। यह नया मॉडल बेहतर टेक्नॉलजी, नई डिजाइन और अडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स से लैस है। वोल्वो की नई एक्ससी90 लम्बरी एसयूवी सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क स्थापित करने का दावा करती है। इसके लुक और डिजाइन की बात करें तो एक्सटीरियर में नई ग्रिल, नया फ्रंट बंपर, नए फेंडर, 20 इंच के अलॉय व्हील, नई हेडलाइट्स और टेललाइट्स और मलबेरी रेड जैसे कलर विकल्प दिए गए हैं।

ईटीरियल जबरदस्त

नई वोल्वो एक्ससी90 के नए ईटीरियर में मॉडर्न स्कैंडिनेवियाई डिजाइन दिखता है। इसमें एक हॉरिजेंटल डैशबोर्ड है, जिसमें प्रीमियम रिसाइकल्ड मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। नए वर्टिकल एयर वेंट्स और बेहतर एंजिंअट लाइटिंग इसके ईटीरियर को काफी जबरदस्त बनाते हैं। नई एक्ससी90 में नया 11.2 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें बेहतर रेजॉल्यूशन और अपडेटेड यूजर इंटरफेस है। बाकी इसमें बेहतर साउंड इन्सुलेशन, अपग्रेडेड स्टीयरिंग व्हील और बेहतर वायरलेस फोन चार्जर भी शामिल हैं।

कूज कंट्रोल

वोल्वो कार इंडिया की फ्लेगशिप एसयूवी नई एक्ससी90 में अडवांस्ड एयर क्लीनर, एंजिंअड ऑटो और एम्पल कार प्ले, प्रीमियम साउंड सिस्टम, अडैप्टिव कूज कंट्रोल, पायलट असिस्ट, लेन कीपिंग ऐड, ब्लाइंड स्पॉट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कोलिजन मिटीगेशन सपोर्ट, 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग असिस्टेंस, वोल्वो कार्स ऐप, ग्राफिकल हेड-अप डिस्प्ले, वॉटिलेटेड मसाज फ्रंट सीट्स, नप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, एयर सर्क्यूलेशन समेत और भी खूबियां हैं।

हिंदुस्तान जिंक 30% महिला कर्मियों का लक्ष्य हासिल करेगा

नई दिल्ली। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) ने बुधवार को कहा कि वह 2030 तक 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हासिल करने की राह पर है। इस समय हिंदुस्तान जिंक में 25 प्रतिशत से अधिक महिला कार्यबल हैं। उद्योगों में लैंगिक विविधता के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। कंपनी का दावा है कि वह भारत की पहली कंपनी है, जिसके पास महिला भूमिगत खदान प्रबंधक हैं। कंपनी ने देश में सबसे पहले महिला भूमिगत खदान बचाव दलों की स्थापना की है। कंपनी की चेरपरसनल प्रिया अग्रवाल हेब्वार ने कहा।

स्मार्ट बाजार ने 5 दिवसीय महिला दिवस समारोह की शुरुआत की

मुंबई। इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, स्मार्ट बाजार अपने स्टोर पर पांच दिनों की मजेदार गतिविधियों, खरीदारी और शानदार ऑफर के साथ समारोह को और भी शानदार बना रहा है। यह समारोह बुधवार 5 मार्च से शुरू होकर 9 मार्च, रविवार तक चलेगा, जिसमें हर दिन रोमांचक कार्यक्रम, सेलिब्रिटी कार्यक्रम और पूरे भारत में 900 से ज्यादा स्मार्ट बाजार स्टोर पर ब्लॉकबस्टर ऑफर और डीलेंस होंगी।

यह पहले कभी न देखा गया उत्सव है। आप मास्टरक्लास में शामिल हो सकते हैं जहाँ आप कुछ नया सीख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए मजेदार गेम खेल सकते हैं या बस सभी बेहतरीन ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, चुनिंदा स्टोर और टॉप आरजे में कुछ शीर्ष प्रभावशाली लोगों से मिलें। सौदे को और भी बेहतर बनाने के लिए शीर्ष ऑफर का लाभ उठाएँ। महिलाओं के कपड़ों की रेंज पर 2 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ और क्लोथिंग और जिवामे जैसे शीर्ष बांड की ह्रा पर 1 खरीदें 2 मुफ्त पाएँ के साथ अपने वॉर्डरोब को नया रूप दें। क्या आप सौंदर्य पाना चाहते हैं? सौंदर्य प्रसाधन पर 1 खरीदें और 1 मुफ्त पाएँ, फेस क्रीम और फेस वॉश



लिए शीर्ष ऑफर का लाभ उठाएँ। महिलाओं के कपड़ों की रेंज पर 2 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ और क्लोथिंग और जिवामे जैसे शीर्ष बांड की ह्रा पर 1 खरीदें 2 मुफ्त पाएँ के साथ अपने वॉर्डरोब को नया रूप दें। क्या आप सौंदर्य पाना चाहते हैं? सौंदर्य प्रसाधन पर 1 खरीदें और 1 मुफ्त पाएँ, फेस क्रीम और फेस वॉश

पर 50 प्रतिशत की छूट। हैयर ड्रायर और स्ट्रेटर के साथ अपने स्टायलिंग गेम को अपग्रेड करें, जिसकी शुरुआती कीमत सिर्फ रु. 599 है। खरीदारी का मजा यहीं नहीं रुकता। महिलाओं के हॉलिवुड पर रु. 160 की छूट, स्टेफी झॉइ मैक्स 42s सेलिटरी नेपकिन पर रु. 230 की छूट और सोफी एंटी बैटरीरिया एक्सएल 48 एक्सएल +44 सेलिटरी पेड पर रु. 65 की छूट पाएँ। इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने दोस्तों के साथ स्मार्ट बाजार में जाएँ और पाँच दिनों तक खरीदारी, मनोरंजन और शानदार बचत का मजा लें। क्योंकि आपको खुद की सेलिब्रेट करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। 5 से 9 मार्च तक स्मार्ट बाजार में हमारे साथ जुड़ें।

कार्यालय नगरपालिका परिषद् रामानुजगंज जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

क्रमांक/311/ले.नि.शा./न.पं./2025 रामानुजगंज, दिनांक 05/03/2025

ई-प्रोक्युरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

पंजीकृत पंजीयन प्रणाली द्वारा जारी सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑन-लाईन निविदा आमंत्रित किया जा रहा है।

क्र.	सिस्टम टेंडर क्र.	कार्य का विवरण	अनु. लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि	निविदा करने की अंतिम तिथि	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1.	165483	विभिन्न वर्डों में 09 नग सामुदायिक/सर्वजनिक शौचालय मरम्मत कार्य	25.64	19500.00	01.04.2025	04.04.2025

उपरोक्त कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञापित निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-पोर्टल <http://eproc.cgstate.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है, एवं विभागीय वेबसाइट <http://cg.uad.gov.in> पर देखा जा सकता है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् रामानुजगंज
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited
(A Government of Chhattisgarh Undertaking) (ISO 9001:2015 Certified)
1st Floor, Udyog Bhawan, Ring Road No. 1, Telibandha, Raipur (C.G.)-492006
CIN: U45203CT1981SG001853, PAN: AABCM6288N, GST Regn No. 22AABCM6288N5ZY
Phone: 0771-6621000 Fax: 0771-2583794
Website: www.csidc.in, Email address: csidc.cg@nic.in, csidc_raipur@yahoo.com

NOTICE INVITING TENDER (2nd call) (Through e-Procurement Portal Only)

No.: 26 /CSIDC/E.E.Division-II/2024-25/ Raipur, dated 03/03/2025
Online tenders are invited in Form-B Item rate basis, from "A" class Electrical license contractors' Registered in D & Above class in new registration system & Unified Registration System - (e-Registration) with Chhattisgarh P.W.D website <https://eproc.cgstate.gov.in> at appropriate class, for the following works:-

S. No.	Name of Work	Class of Contractor Eligible to Tender	Time allowed including rainy season	Estimated Cost (INR Lacs)	EMD (INR Rs.)	Cost of Tender Doc. (INR) including GST 18%
1	External Electrification Work for Electricity Connection of O.H.T./Pump House/Site Office and Street Light at Industrial Kesda, Tah.-Simga, Distt. Baloda Bazar (Bhatapara) (C.G.)	Registered in D class in new registration system - Unified Registration System - (e-Registration)	02 Month	20.85 Lacs	15700/-	885/-

The tender document and other details can be downloaded from the web portal (website) <https://eproc.cgstate.gov.in> from 04/03/2025 and shall be submitted online only. Amendment in tender, if any, will only be uploaded on the website and shall not be published in any newspaper.

NOTE: 1) The interested tenderers for online submission of tender may contact CG eProc Helpdesk. Operated by Mjunction Services Limited., they may reach Helpdesk using 18002582502 (from 9 AM to 11 PM) (therein press 2 for CG e-Proc) or you can email them at Helpdesk.eproc@cgswan.gov.in. 2) Tenderer may contact to E.E., Div-I, CSIDC, Udyog Bhawan in working hours to clear their doubt if any before online submission of the tender.

Executive Engineer,
Division-II

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर

(केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ) ई - प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना

Main Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

स. क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक/दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
1	165335 द्वितीय निविदा 03.03.2025	लोहपडीगुड़ा जिला बस्तर में 100 सीटर आवासीय विद्यालय भवन, विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। जमा मद।	207.95
2	165336 द्वितीय आमंत्रण 03.03.2025	जिला जशपुर के वि.ख. कांसाबेल के कोटानपानी चौक से तिलंगा चिकनीपानी पहुँच मार्ग लं. 6.60 कि.मी. पुल-पुलिया सहित निर्माण कार्य।	751.79
3	165338 द्वितीय आमंत्रण 03.03.2025	जिला बस्तर के टाहकावाड़ा से पटेलनारा मार्ग के कि.मी. 1/6 में। जीरम नदी पर उच्चस्तरिय सेतु निर्माण कार्य का शेष कार्य।	231.39
4	165339 द्वितीय आमंत्रण 03.03.2025	सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. अंतर्गत जिला सुकमा के कांजीपानी से विपुलपार मार्ग के कि.मी. 2/4 में गोरली नदी पर उच्चस्तरिय पुल निर्माण कार्य का शेष कार्य।	260.02
5	165342 द्वितीय आमंत्रण 03.03.2025	नारायणपुर तालाब के पास से सुरना (चुरेदा) मेन रोड तक पहुँच मार्ग लंबाई 1.85 कि.मी. का निर्माण कार्य।	214.51
6	165362 द्वितीय आमंत्रण 03.03.2025	1) जिला जशपुर के सिसरिगा से मछलंग हट्टे हट्टे सहसपुर पहुँच मार्ग लं. 6.50 कि.मी. का निर्माण कार्य। 2) जिला जशपुर गोर्दी से पालोडीह पहुँच मार्ग लंबाई 3.10 कि.मी. का निर्माण कार्य।	1054.14
7	165364 तृतीय आमंत्रण 03.03.2025	जिला सुकमा के गौदीरा से राउतपारा मार्ग के कि.मी. 1/4 में मलगेर नदी पर उच्चस्तरिय पुल निर्माण कार्य का शेष कार्य।	264.93
8	165368 द्वितीय आमंत्रण 03.03.2025	1) जिला जशपुर के ग्राम पंचायत चंदामढ़ भेसांगुड़ा बस्ती से बटाराबहार चन्द्रपुर पहुँच मार्ग लंबाई 4.00 कि.मी. 1/4 में फुल नदी पर उच्चस्तरिय सेतु निर्माण कार्य का शेष कार्य। 2) जिला जशपुर के वि.ख. कांसाबेल के दोकड़ा से कोरंगाबहला पहुँच मार्ग लंबाई 4.00 कि.मी. पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य।	805.39
9	165371 द्वितीय आमंत्रण 03.03.2025	सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. अंतर्गत जिला सुकमा के बोक्लाघाट से कांजीपानी मार्ग के कि.मी. 1/4 में फुल नदी पर उच्चस्तरिय सेतु निर्माण कार्य का शेष कार्य।	314.94
10	165377 द्वितीय आमंत्रण 03.03.2025	सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. अंतर्गत जिला सुकमा के विन्नापार से जीरमपार मार्ग के कि.मी. 3/4 पर मलगेर नदी पर उच्चस्तरिय सेतु निर्माण कार्य का शेष कार्य।	270.67

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि सं.क. 07 दिनांक 17.03.2025 निर्धारित है। एवं अन्य शेष निविदाओं के लिए दिनांक 20.03.2025 निर्धारित है। निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाइट में देखे जा सकते हैं।

मुख्य अभियन्ता
केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर

STATE URBAN DEVELOPMENT AGENCY 4th Floor, D-Block, Indrawati Bhavan (HOD Building), Nava Raipur Atal Nagar, Chhattisgarh 492002 Phone 0771-2222401,02 Fax 0771/2222409 Email: osd.suda@yahoo.com

Notice Inviting Tender

RFP No.9/SUDA/SBM/01/2024-25/8389 Nava Raipur, Atal Nagar, Dated 03/03/2025
Sub: Request for Proposal (RFP) for Selection of consulting firms for Preparation of Detailed Project Report (DPR), conducting EIA studies, Public Hearing, obtaining Environment Clearance, Consent to Establish, consent to operate, Procurement & Bid Process Management and Provide Supervision & Monitoring Services for development of District level regional Sanitary Landfill Facilities for ULBs in the State of Chhattisgarh (2nd Call)
The State Urban Development Agency (SUDA) Chhattisgarh, as the Mission Directorate for implementing all centrally sponsored schemes of urban development in the state, is inviting proposals in conformity with the RFP document in a single stage three bid envelope (Envelope 'A': Bid Document Fees & Earnest Money Deposit, Envelope 'B': Technical Bid and Envelope 'C': Financial Bid) from registered and authorized agencies having experience and expertise in the similar field of work as per the criteria mentioned in the RFP document

System Tender No.	Name of the Work	EMD	RFP Document Fee
165439	Request for Proposal (RFP) for Selection of consulting firms for Preparation of Detailed Project Report (DPR), conducting EIA studies, Public Hearing, obtaining Environment Clearance, Consent to Establish, consent to operate, Procurement & Bid Process Management and Provide Supervision & Monitoring Services for development of District level regional Sanitary Landfill Facilities for ULBs in the State of Chhattisgarh (2nd Call)	INR 5,00,000/-	INR 10,000/-

1. The details can be viewed and downloaded online from the e-procurement portal "<https://eproc.cgstate.gov.in>". 2. All eligible/interested Bidders are mandated to get enrolled on e-procurement portal. 3. Bidders can contact Help Desk for any clarification of their doubts regarding the process of electronic procurement system. Help Desk toll free number 18004199140 or through email ID helpdesk.eproc@cgswan.gov.in. 4. The RFP can be postponed or cancelled at any time due to administrative reasons and no claim shall be entertained on this account. 5. Modifications/Amendments/Corrigendum, if any shall not be advertised in the newspaper but shall be published in e-procurement portal "<https://eproc.cgstate.gov.in>". 6. The eligible bidder may submit their bid along with EMD as detailed in RFP document. 7. The Bidder must submit their bid online on e-procurement portal "<https://eproc.cgstate.gov.in>" on or before 19/03/2025 by 5:00 PM. The eligible bidder may submit their bid online only and physical submission of original EMD, RFP document through speed post/registered post only.

-SD/-
Chief Executive Officer
State Urban Development Agency,
Nava Raipur Atal Nagar

S-43124

कृषि मौसम विज्ञान विभाग
Department of Agricultural Meteorology
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya
कृषक नगर, रायपुर - 492012 Krishak Nagar, Raipur - 492012
(C.G.) Ph. (O) - 0771-2442557 Fax - 0771-2442557,
Email-rpr.aicrpam@gmail.com

क्रमांक/कृषीवि/2024-25/1071 रायपुर, दिनांक: 03/03/2025

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित अखिल भारतीय समन्वित कृषि मौसम अनुसंधान परियोजना, कृषि मौसम विज्ञान विभाग रायपुर में संविदा नियुक्ति पर भेदोलाजिकल आब्जर्वर (रु 23350/- प्रतिमाह) हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28 मार्च 2025 तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igkv.ac.in पर उपलब्ध है।

विभागाध्यक्ष
कृषि मौसम विज्ञान विभाग
रायपुर (छ.ग.)

संवाद-43121

कार्यालय अधिष्ठाता,
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)
Bendrachuwa, Raigarh, Chhattisgarh, ph-07762-215619
E-mail: gmcraigarh.2013@gmail.com

क्रमांक/चिकि.महा./क्रय/ 2024-25/2247 रायगढ़ दिनांक 04/3/25

// ई-निविदा निरस्तीकरण सूचना //

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ विभिन्न विभागों के लिए Chemical, Kit, Reagent & Glassware Items क्रय किये जाने के संबंध में दर अनुबंध (Rate Contract) करने हेतु इच्छुक फर्म / प्रदायकर्ता फर्म / अधिकृत विक्रेता फर्म / निर्माता कम्पनियों से छत्तीसगढ़ शासन के वेब साइट www.eproc.cgstate.gov.in द्वारा कार्यालयीन निविदा पत्र क्रमांक / चिकि.महा./ क्रय/ 2024-25/5334 रायगढ़ दिनांक 10.06.2024 (E-Tender No. 155016) के माध्यम से खुली ई-निविदा आमंत्रित किया गया था, जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।

अधिष्ठाता
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शास. चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

जी-242505752/1

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

ई प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना

eProcurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 20-03-2025 समय 17:30 तक ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

सिस्टम निविदा क्रमांक	निविदा सूचना क्रमांक एवं दिनांक	कार्य का नाम	निविदा की लागत (लाख में)	आमंत्रण का क्रमांक
165355	28/व.ले.लि./2024-25 दिनांक 03.03.2025	भुलमुड़ा जलाशय योजना का जीर्णोद्धार कार्य।	84.22	द्वितीय आमंत्रण

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्युरमेंट वेब साइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर दिनांक 10-03-2025 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते हैं।
नोट: निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्युरमेंट वेबसाइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियन्ता
जल संसाधन संभाग रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जी-242505763/2

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 2 (छत्तीसगढ़)

ई-प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना

दिनांक 04.03.2025
निम्नांकित कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा "डी" श्रेणी एवं अधिक श्रेणी के ठेकेदारों हेतु निविदा माह जनवरी 2025 को आमंत्रित की गई थी, किंतु नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव की अदर्श आचार सहिता प्रभावशील होने के कारण उक्त दोनों कार्यों का प्रकाशन समाचार पत्रों में नहीं हो पाया था, जिससे उक्त कार्यों की निविदा डाउनलोड करने की तिथि में संशोधन कर दिनांक 19.03.2025 तक की जाती है।

एन.आई.डी. क्र. / निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
NIT NO. 431 Tender No. 164744	जिला धमतरी के कुरुद में संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्त महाविद्यालय कुरुद में 8 नए अतिरिक्त कक्षा का निर्माण कार्य।	रु. 197.47 लाख
NIT NO. 432 Tender No. 164876	पी.एम. उष्मा के तहत जिला धमतरी के अंतर्गत बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी में नवीनीकरण एवं उन्नयन कार्य।	रु. 40.00 लाख

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञापित निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्युरमेंट वेब पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है। (राशि रु.100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित पत्र में शपथ-पत्र एवं न्यूनतम राशि रु. 10.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एनेक्चर-3 का शपथ पत्र बिड केपेसीटी उपलब्धता बाबत जानकारी एवं अन्य जानकारी एनआईडी के 2.10 में संलग्न संशोधित प्रश्नानुसार प्रस्तुत करें।)

निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय खसरीसंग
आपकी थी चाह, हमने बनाई राह
अधीक्षण अभियन्ता,
लो.नि.वि.रायपुर

बिलासपुर, गुरुवार 6 मार्च 2025

haribhoomi.com

प्रथम पृष्ठ का शेष

भारतमाला...बड़ा...

में राज्य शासन को 8 अगस्त 2022 को कृष्ण कुमार साहू और हेमंत देवानों ने शिकायत की थी कि भारत माला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापटनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा बांटने के नाम पर अधिकारियों ने पैसे की बंदरबाट की। उनकी जमीन का खसरा बदल दिया गया। पूर्व खसरे पर उस राशि का भुगतान दिख रहा है। शिकायत के बाद रायपुर कलेक्टर को जांच करने के निर्देश जारी किए गए। शासन के निर्देश पर कलेक्टर ने कमेटी बनाकर जांच कराई। अमनपुर इलाके में पदस्थ तत्कालीन अधिकारियों ने जमीनों के खसरे में हेरफेर करके संबंधित इलाके में 25.5 करोड़ की जगह 78 करोड़ का भुगतान कर दिया। मुआवजा घोटाले की जांच रिपोर्ट शासन को जुलाई 2024 में भेज दी गई थी, जिसमें घोटाले की पुष्टि की थी। घोटाले में शामिल अफसरों से शासकीय राशि की वसूली करके का जिक्र भी किया था। रिपोर्ट के आधार पर शासन ने अब कार्रवाई शुरू की है।

246 करोड़ का...

मुआवजा राशि निर्धारित की गई। इसमें से 246 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। वहीं 78 करोड़ रुपए का भुगतान अभी रोक दिया गया है।

सर्वे के ठीक...

पर बांट दी गई। इसके बाद एक ही परिवार के सदस्यों को 70 करोड़ रुपए मुआवजा का भुगतान कर दिया गया। जांच अधिकारियों ने तत्कालीन अफसरों की इस कार्यप्रणाली का सीधा जिक्र अपनी जांच रिपोर्ट में किया है।

भारतमाला प्रोजेक्ट...

17 और आरंभ संभाग के दो गांव की भूमि का अर्जन किया गया है।

भारतमाला प्रोजेक्ट का...

किया गया है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंदाकर ने भी इसे व्यवस्था का प्रश्न बताते हुए पत्रा प्रेषित किया था। मामले में आसदी से विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा, यह अत्यंत खेदजनक है। संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित करता हूँ कि सभी अधिकारियों को निर्देशित करे कि सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखकर उत्तर सही ढंग से देना चाहिए। साथ ही इसे अगले हफ्ते के पहले प्रश्न के तौर पर लिए जाएं। अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद अब इस सवाल को दूसरी

बार अगले सप्ताह के लिए लिया गया है।

राज्या बोली-तस्कर...

इसने एयरपोर्ट पर रात की मदद की थी। पुलिस ने इस कार्टेबल का भी बयान दर्ज किया है। दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट से केआईए पर उतरने के बाद अग्निशो रण्य ने अपने साथ आए पुलिस कार्टेबल बसवराजू की मदद से सुरक्षा जांच को दरकिनार करने की कोशिश की। हालांकि, डीआरआई को उसकी गतिविधियों के बारे में पता चल गया था और उसे सोने की खेप के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। तलाशी लेने पर अधिकारियों को उसकी जैकेट के अंदर 12.56 करोड़ रुपए की कीमत का 14.2 किलोग्राम विदेशी सोना मिला। गिरफ्तारी के बाद रात रात को आगे की जांच के लिए नागवारा स्थित डीआरआई कार्यालय ले जाया गया। जांच में पता लगा है कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से बचने के लिए उन्हें अक्सर पुलिस एस्कॉर्टर्स मिलते थे।

जिप दुर्ग में...

भाजपा के उम्मीदवार सरस्वती बंजारे के विरोधी जीत की घोषणा कर दी गई। बारह सीट वाले जिला पंचायत में एससी वर्ग से भाजपा के सरस्वती बंजारे और कांग्रेस से उषा सोनवानी उम्मीदवार थीं। दुर्ग के राजीव भवन में सप्ताहभर पहले पर्यवेक्षक सुबोध हरितवाल की उपस्थिति में कांग्रेस से जिलाध्यक्ष के लिए उम्मीदवार उषा सोनवानी को बनाया गया था। इसी उम्मीद से पूरे संगठन के नेता बुधवार को जिला पंचायत पहुंचे थे, लेकिन ऐन वक्त में उषा सोनवानी नहीं पहुंची और भाजपा के अध्यक्ष सरस्वती बंजारे विरोधी जीत गई। कांग्रेस को नहीं मिला अपनी का साथ-बारह सीट में कांग्रेस को पांच सीट और भाजपा को छः सीट मिले थे। वहीं एक भाजपा से बानी प्रिया साहू थीं। उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने देवेन्द्र चंद्रवंशी को उतारा था, लेकिन उन्हें सिर्फ चार वोट मिले। अध्यक्ष उम्मीदवार के गायब होने से उनका एक वोट कम हो गया और भाजपा के उम्मीदवार पवन शर्मा सात वोट से जीत गए।

आधा दर्जन शिक्षकों...

की कॉपी संबंधित स्कूलों को मंगलवार को मिली। ट्रांसफर आदेश एक माव की जारी किया गया था। एक माव शनिवार होने की वजह से आदेश को लेटर शका हुई, इसके बाद आदेश की पुष्टि करके मंत्रालय में फोन किया गया, तो ट्रांसफर आदेश फर्जी पाया गया। फर्जी ट्रांसफर स्वीकार करनी करनी किसी की शरारत है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है, पुलिस इस की पड़ताल करने की बात कह रही है। फर्जी ट्रांसफर आदेश में यह है- शिक्षकों का फर्जी ट्रांसफर आदेश जारी किया गया है, वह हबूद सरकारी आदेश की ओरिजनल

आदेश कॉपी की तरह है। आदेश कॉपी में क्रमांक एफ 3-27/ 2025/20 - तीन राज्य शासन एतद द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवकों का स्थानांतरण उनके नाम के समुच्चय करते हुए कालम नंबर 4 में अंकित कर पत्र कालम नंबर 5 में अंकित आधार पर, अस्थाई रूप से आगामी आदेश परत पदस्थ करता है। शिक्षकों के स्थानांतरण का आधार प्रशासनिक बताया गया है।

फर्जी ट्रांसफर आदेश...

कालम नंबर 4 में अंकित स्थान पर कालम नंबर 5 में अंकित आधार पर, अस्थाई रूप से आगामी आदेश परत पदस्थ करता है। शिक्षकों के स्थानांतरण का आधार प्रशासनिक बताया गया है।

महिला पंचों की...

सिंह ठाकुर पर यह कार्रवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (सीईओ) कबीरधाम अजय कुमार पिपारी द्वारा की गई है। जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत परसवारा में 3 माव की नवनिर्वाचित पंचों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें विधवा द्वारा अपने पदवी दाखिलों के निवेदन में गंभीर लापरवाही बरतना पाया गया।

जांच में माना...

पंचायत पंडरिया में संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

एक्सट्रा इयूटी खत्म होगा...

संघ लगना मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि वहां शराब छग की तुलना में काफी सस्ती है और यहां कमी आई भी तो सिर्फ 9 फीसदी तक की ही संभव है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में एस्ट्रा इयूटी को समाप्त किए जाने के साथ ही प्रदेश में शराब की कीमतों में 40 रुपए से 3 हजार रुपए तक की कमी आएगी। 1 अप्रैल से नई दर लागू होने जा रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड में ठेकेदारी प्रथा लागू है। इसके अलावा शराब की कीमतों की कम है। यहीं नहीं दिल्ली और हरियाणा से भी व्यापक पैमाने पर यहां शराब की तस्करी की जा रही है। इसकी वजह से ठेकेदार ज्यादा से ज्यादा माल खपाने के लिए छत्तीसगढ़ में कालाबाजारी कर बेचने की फिरेक में रहते हैं। इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ में पड़ा है। छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए की शराब प्रतिवर्ष खपाई जा रही है। इससे निपटने के लिए 2 मार्च को केबिनेट की बैठक में सरकार ने निर्णय लिया कि अंग्रेजी शराब पर लगने वाले 9.5% आबकारी शुल्क को खत्म किया जाए। इससे हर बोतल पर 40 रुपए से 3 हजार रुपए तक दाम घट जाएंगे। इसके आधार पर ही आबकारी विभाग

ने नई नीति तैयार की है। साल 2025-26 की आबकारी नीति पिछले साल यानी 2024-25 की तरह ही है। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ अब प्रदेश में दिल्ली और हरियाणा से भी महंगी विदेशी शराब की व्यापक पैमाने पर तस्करी हो रही है। सादे नौ फीसदी दाम कम करने के बाद भी दामों में बड़ा अंतर होने के कारण इन प्रदेशों से शराब की आवक यथना असंभव दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रति बोतल दो से दहाई हजार रुपए तक का अंतर है।

ठेकेदार दे रहे 40 फीसदी ...

कि पड़ोसी राज्यों से शराब की आवक ज्यादा होने से छत्तीसगढ़ के आबकारी राज्य को हर माह करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। जानकारी की मानें तो जब छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें निजी हाथों में थीं उस दौरान यहां के ठेकेदार तुलाने ऑफर देकर पड़ोसी राज्यों में तस्करी कराते रहे हैं।

कार्रवाई के लिए...

हो जाते हैं। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण आबकारी महकमे के पास पर्याप्त स्टॉक नहीं होना है।

कम नहीं होगा...

2025-26 में 674 मदिरा दुकानें और प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने की तैयारी है। देशी शराब का आपूर्ति पहले जैसी ही रहेंगी और पुरानी कीमत पर ही उपलब्ध होगी। विदेशी मदिरा थोक कय, वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। मदिरा पर लागू अधीसंरचना विकास शुल्क भी जिस तरह पहले लगता था, उसी तरह से लगेगा।

हाई रेंज की शराब...

1100-1300 रुपए में बिक रही है। रेड लेबल 2700 और ब्लैक एंड वाइट 2000-2300 रुपए में बिक रही है। नई दर लागू होने से इन सभी की कीमतों में लगभग 10 प्रतिशत तक कमी आएगी।

भारत और चीन के...

में अपने दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस को

पहली बार संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, भारत हमसे 100 प्रतिशत से अधिक आंटी शुल्क वसूलता है। फरवरी में राष्ट्रपति टुप ने कहा था कि उनका प्रशासन आधर पर अवार्ड पास कर रहे हैं वह भी नहीं बता रहे हैं और ना ही भूमि अधिग्रहण अवार्ड की प्रति दी गई है। इसके विपरीत कई किसानों की जमीनों पर अर्द्ध कच्चा जिनल स्टील एंड पावर लिमिटेड के द्वारा सितंबर अक्टूबर 2024 से कर दिया गया है।

49 किसानों की ...

को चुनौती दी है। याचिका में इस बात को भी चुनौती दी गई है, कि जो मुआवजे का निर्धारण किया जा रहा है वह 2010 के अधिसूचना की दूरी के आधार पर किया जा रहा है जबकि 15 साल में जमीनों के भाव बहुत बढ़ गए हैं। हाईकोर्ट में चंदन सिंह सिद्धा समेत 49 किसानों जिसमें अधिकतर आदिवासी समुदाय के हैं द्वारा लगाई गई याचिका पर प्राथमिक सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि गारे फोर बाई सिक्स कॉल ब्लॉक का भूमि अधिग्रहण 2024 सितंबर में शुरू किया गया है, परंतु इसका खनन पट्टा 2023 में ही जारी कर दिया गया है। यह संविधान की धारा 300 ए का खुला उल्लंघन है क्योंकि किसी भी निजी भूमि को बिना विधिवत कानून के अधिग्रहण कर मुआवजा दिए बनेर उसे जमीन का अधिकार किसी और को नहीं सौंपा जा सकता।

भू अधिग्रहण की...

संविधान की धारा 254 के अनुसार यदि संसद के द्वारा किसी क्षेत्र में कानून बना दिया गया है तो उसे क्षेत्र पर राज्य विधानसभा की ओर से बनाए गए कोई कानून

हरिभूमि 6

बच्चों के सभी ऑपरेशन किये जाते हैं।
आयुष्मान कार्ड/राशन कार्ड द्वारा ऑपरेशन संभव
9 आमा सिवनी, विधानसभा रोड, रायपुर (छ.ग.) 7987225800, 9301744425

अष्टविनायक डॉ. रितेश रंजन
(MCH, पीडियाट्रिक सर्जन)
मोतियाबिंद
आयुष्मान कार्ड सुविधा
साई बाबा नेत्र हॉस्पिटल
छोटी लाईन ब्रिज के पास, फाफाडी, रायपुर 9644099925

लकवा, कमर दर्द, गर्दन दर्द, सायटिका, गठियावात, हड्डीदर्द, झुनझुनी वात, घुटनों का दर्द एवं सभी प्रकार के वात रोग, मोच, सूजन एवं मुठमार दर्द, एड़ी दर्द एवं सभी प्रकार के मांसपेशियों, नाड़ियों जैसे पोलियो अर्द्धगवात, अस्थिभंगन, अस्थि शूल, टूटी हुई हड्डी व कमजोर हड्डीयों को मजबूती प्रदान करता है, रक्त में संचार बढ़ा कर अस्थियों को क्रियाशील बनाता है
नकली माल से सावधान

epaper- www.haribhoomi.com

Classified

Email- hbcclassified375@gmail.com

आवश्यकता आपकी सुविधा हमारी

Contact For Advertisement Booking

Ring Road No.-2, Gourav Path, Bilaspur

Mo.- 9826782100, 9754263022

आवश्यकता है

आवश्यकता है- विद्यालय में कार्य करने हेतु टीचर्स प्लग गाई एवं मार्केटिंग हेतु फ्रेशर लड़के/लड़कियाँ की आवश्यकता है। मिलने का समय सुबह 9 से 2 बजे। संपर्क - संस्कार स्कूल बाजार के सामने उसलापुर 7440 549466, 7000737657 (370399)

आवश्यकता है- स्या एण्ड सेलुम में काम करने के लिए तोरवा और व्यापार विहार में महिला टेलीकॉलर, महिला थैरैपिस्ट एवं महिला हाउस कीपिंग की आवश्यकता है। वेतन योग्यतानुसार। संपर्क करें 6399166000 (37041)

आवश्यकता है- सर्वमंगला टैट हाउस में कार्य हेतु मैनेजर, लड़कों, एवं अनुभवी ड्राइवर, की आवश्यकता है। वेतन योग्यतानुसार सम्पर्क करें - कुम्हार पारा रोड राजीव गांधी चौक बिलासपुर, 62602 73334, 9826601147 (37040)

आवश्यकता है- मंत्रा इलेक्ट्रीकल ऑटो शोरूम में निम्न पदों की आवश्यकता है। सेल्समैन- 5, मैकेनिक- 5, ड्राइवर- 2, हेलपर- 5 सम्पर्क करें- 9039140362, 73891 45700, 7898869370, 9303555032 (37038)

आवश्यकता है- इलेक्ट्रीकल दुकान में बिजली कीपिंग एण्ड फिटिंग साईड में कार्य हेतु लड़के एवं कम्प्यूटर वर्क के लिये लड़की एवं लड़के का आवश्यकता है। अरुण इलेक्ट्रीकल चंद्रा पार्क के सामने चूड़सिंह बाजार रोड मो. 7869102080 (37043)

आवश्यकता है- सुरक्षा गार्ड की तत्काल भर्ती बिलासपुर पुराना बस स्टैंड, कोनी, तिरफा, सिरिगट्टी, व्यापार विहार, बिल्वा मोड, हिरि हेतु आवास मुक्त बाँधोडाटा के साथ सम्पर्क करें वेतन 9000- 12000 मो. 9999336942, 9589316942 (37037)

आवश्यकता है- होलसेल सजिकल शॉप में काम करने हेतु लड़के, लड़कियाँ एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर, सेल्समैन, वर्कर, ड्राइवर की आवश्यकता है अनुभव की प्राथमिकता है सम्पर्क करें- श्री साई गुरु सर्जिको बिलासपुर 07752 403024, 9827165932 (37033)

आवश्यकता है- OMI कम्पनी में लड़के, लड़कियों की आवश्यकता है योग्यता 10वीं से मेजुएट, उम्र 18 से 28, आय 8500 से 18000+ रहना खाना सम्पर्क करें- न्यू बस स्टैंड, बिलासपुर 88188 77406, 9644433021 (37031)

आवश्यकता है- अनुभवी नशाभुक्त कार ड्राइवर की आवश्यकता है वेतन 15000 प्रतिमाह सम्पर्क करें- लक्ष्मण सीमेंट सदर बाजार, करीना चौक बिलासपुर (36997)

आवश्यकता है- सीमेंट की मार्केटिंग करने हेतु अनुभवी सेल्समैन की जो उवर्ष का अनुभव हों को प्राथमिकता आकर्षक वेतन योग्यता अनुसार सम्पर्क ममता ट्रेडर्स मौपका बिलासपुर मो.- 9993443207. 93003 07926 (37042)

आवश्यकता है- थोक दवाई दुकान में माल निकालने/ जमाने हेतु लड़कियों, पैकिंग कार्य हेतु लड़को की आवश्यकता है अनुभवी को प्राथमिकता (वेतन योग्यतानुसार) संपर्क करें- सेल्समैन मेडिकल एजेंसी मेडिकल कॉम्प्लेक्स तेलीपारा (3350)

आवश्यकता है- ग्रीनी स्ट्रेंड्स दुकान में काम करने के लिए लड़के एवं लड़कियों की आवश्यकता है पता- नरेश बाजार के बगल में तेलीपारा बिलासपुर सम्पर्क करें- 9300111207 (37030)

आवश्यकता है- शादी भवन में हाऊस कीपिंग एवं सफा- सफाई हेतु आवश्यकता है परिवार वाले को प्राथमिकता (रहने की सुविधा प्री) संपर्क- हरि-अमृत मैरिज रिसोर्ट सीपत मेनरोड मोपका बिलासपुर मो- 98271-14005 मिलने 98271-14005 (37035)

आवश्यकता है- फिनाईल फेक्ट्री में कार्य करने हेतु लड़को आवश्यकता है रहने की सुविधा एवं अन्य सुविधा संपर्क करें डे कैमिकल इण्डस्ट्रीज बिलासपुर मो. 8319781220, 98930 13099 (37027)

आवश्यकता है- कपड़ा दुकान में काम करने हेतु यंग लड़कों की आवश्यकता है। सम्पर्क करें- नेमा कम्पनी सिटी कोतवाली के सामने बिलासपुर 7898958865 (37023)

आवश्यकता है- बिलासपुर के प्रतिष्ठित अस्पताल एवं औद्योगिक संस्थानों हेतु भारी मात्रा में सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है अपने मूल दस्तावेजों सहित सम्पर्क करें- F3, अम्य प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, PNB बैंक के ऊपर हाईटेक बस स्टैंड के सामने तिरफा बिलासपुर 89627 97916, 9981614171 (37034)

आवश्यकता है- कंस्ट्रक्शन ऑफिस काम करने हेतु लड़कियों की आवश्यकता है सम्पर्क करें- प्रागति कंस्ट्रक्शन सीट देवी पेट्रोल पम्प के सामने शिवम अस्पताल के पास, सीपत रोड मोपका बिलासपुर 9827979016, 95227 69593, 7225906399 (37029)

आवश्यकता है- कैटरिंग सर्विस में कार्य करने हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर, फीलड मार्केटिंग एवं वर्कर की आवश्यकता है। वेतन योग्यता अनुसार। सम्पर्क करें साई कैटरिंग सर्विस, जबड़ापारा सरकंडा, बिलासपुर 93298 03725 (37016)

आवश्यकता है-टेलीकॉलिंग, फोटोशॉप, कम्प्यूटर ऑपरेटर लड़के, लड़कियों की आवश्यकता है योग्यता 12वीं से स्नातकोत्तर, वेतन 7000 से 9000 सम्पर्क करें- पब्लिशिंग नूतन चौक सरकंडा बिलासपुर 7974794530 (37022)

आवश्यकता है-तीन साल के बच्चे का समस्त कार्य करने हेतु बिलासपुर में एक लड़की/ महिला का आवश्यकता है वेतन योग्यता अनुसार सम्पर्क करें- 9826307980, 869980 67737 (37021)

आवश्यकता है-सर्जिकल ऑफिस में कार्य हेतु लड़को (बाइक अनिवाह) समान समय- सुबह 9:30 से 2 एवं शाम 4 से 6 (37035)

आवश्यकता है- बम्पर पार्टी OMMI मल्टीनेशनल कम्पनी को 140 से अधिक लड़के, लड़कियाँ की आवश्यकता है आय 10500 से 18500 प्रतिमाह आवास, खाना प्री परमानेंट जॉब पता- दीपसागर कोतली बिलासपुर 80034 02269, 9519393913 (36922)

Required-English medium passout Teacher's required Chemistry XI, XII, S.st, English IX, X, 2-3 hour job. Salary 10k-15k Winner's Academy Tuition classes in rajkishor nagar Bilaspur Wats app your resume 8839746460 (37020)

Required-Teachers Wanted postgraduate & graduate trained teachers for the following Subjects Mathematics Physics Chemistry, Biology, Accountancy, Eligible & interested candidates can submit their resume with photo to the principal Nav Jagriti higher Sec. School (English Medium) Block Road, Takhatpur Dist- Bilaspur (C.G.) before 22nd March 2025 (37026)

आवश्यकता है-सीए आफिस में काम करने हेतु चरपरासी (यून) की आवश्यकता है सम्पर्क करें- शाम 4 से 8 बजे तक पलाश पम्पनाई एंड एसोसिएट्स सिन्धु ऑटो स्टोर्स के पास गांधी चौक बिलासपुर (37007)

आवश्यकता है-छत्तीसगढ़ स्टेशनरी एवं बुक डिपो में कार्य करने हेतु लड़कियों एवं बुक डिपो में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है सम्पर्क करें- सरकण्डा, मंगला चौक, भारतीय नगर चौक, बिलासपुर 99071 67890, 9753339324, 62610 84748 (37005)

आवश्यकता है-बेलियाटा द फैमिली सैलून में कार्य करने हेतु अनुभवी हेयर स्टायलिस्ट, हेयर ड्रेसर की आवश्यकता है 4साल कार्य अनुभव अनिवार्य है सम्पर्क करें- सरकण्डा, मंगला चौक, भारतीय नगर चौक, बिलासपुर 99071 67890, 9753339324, 62610 84748 (37005)

आवश्यकता है-किताब दुकान में काम करने हेतु लड़के, लड़कियों की आवश्यकता है। सम्पर्क करें- सुबह 11बजे से शाम 5बजे तक लिवेक बुक डिपो गुरुद्वारा के पास मेन रोड, दालबंद बिलासपुर 989337 8899 (37010)

आवश्यकता है-पाटर्स दुकान में काम करने हेतु युवक, युवती चाहिए कार्य समय सुबह 10बजे से 7:30 बजे सम्पर्क करें- दोपहर 1बजे से शाम 5बजे तक जी.बी. ऑटो, इंदू चौक बिलासपुर 93003 33371 (37008)

आवश्यकता है-व्यापार विहार स्थित हॉटल श्रीश्याम इंटरनेशनल में अनुभवी जनरल मैनेजर एवं तिफरा सब्जी मंडी ऑफिस में कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है वेतन योग्यतानुसार सम्पर्क करें- 9893599044 (सुबह 10 से 1 एवं शाम 5 से 7) (37009)

आवश्यकता है-फैक्ट्री होटल हेतु सुपरवाइजर, सुरक्षागार्ड, लेडीगाई, मार्केटिंग अधिकारी योग्यता 10वीं, स्नातकोत्तर गाई ऊंचाई 5'7" वेतन 12000 से 15000 सम्पर्क-Alert SGS Private Limited, 434, चतुर्थ तल, प्रोमेसिव पॉइंट लालपुर रायपुर 77460 00016, 8720005500 (3160)

आवश्यकता है-इलेक्ट्रीकल दुकान में डाटा एंट्री, एकाउंटिंग एवं सेल्स कार्य हेतु लड़कियों एवं लड़को की आवश्यकता है सम्पर्क करें- सूरज इलेक्ट्रीकल C-21, नेलाजी कॉम्प्लेक्स मन्दिर चौक, जरहाभाटा बिलासपुर 93015 86381, 9827181236 (37011)

आवश्यकता है-होलसेल खिलोना दुकान में काम करने हेतु अनुभवी लड़को की आवश्यकता है जिसे खिलोना दुकान में काम करने, कार्टून पैकिंग का अनुभव हो सम्पर्क करें-तेलीपारा बिलासपुर 771106641, 9753330000 (36813)

आवश्यकता है-बॉयज हॉस्टल में झाड़ पोछा टॉयलेट क्लीनिंग कार क्लीनिंग के लिए मेहनती आरमी की आवश्यकता है रहने की सुविधा 9 से 5 तक इयूटी वेतन 9000/- से योग्यता अनुसार एवं 2BHK नवनिर्मित स्वतंत्र मकान बेचना है। सम्पर्क- घोष एसोसिएट्स 9425220523, 9827875257 (36967)

आवश्यकता है-टेलीकॉलिंग ऑफिस कार्य हेतु महिलाएं युवतियाँ चाहिए योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक समय 9 से शाम 5, सैलरी 5000 से 15000 सम्पर्क करें-स्मार्ट रोड नेहरु नगर गणेश चौक बिलासपुर 7049274510 (1380)

आवश्यकता है- अंजनी बिल्डकॉन में ऑफिस मार्केटिंग व सुपरवाइजर कार्य हेतु लड़के/ लड़कियाँ, टैली कालर हेतु लड़कियाँ/ महिला की आवश्यकता है, संपर्क- निखिल टॉवर शॉप न. 27 सीपत मेन रोड मोपका 6261962696, 98272 09827 (3347)

Wanted- Hiring a Business Development Officer (Manager) /Deputy Manager) Key Responsibilities: *Identify new business opportunities and drive growth *Collaborate with teams on proposals and solutions Requirements: Degree in Business /Marketing or related field Proven 5+ Years of sales experience and strong communication skills Why Join us- Competitive salary & incentives and other benefits Opportunity for career growth Location - Korbha, Champa, Raigarh, Manendragarh Mo. 7970010958 (3351)

बेचना है-बिलासपुर में गोकुल धाम में सर्व सुविधा युक्त 2BHK, 25*40= 1000 वर्ग फीट में बना हुआ नव निर्मित मकान 28 लाख रुपए में बेचना है सम्पर्क करें- 9340252857 (36988)

बेचना है-डायवर्टेड प्लांट 30*58 मेन रोड ऊपर मटियारी, बेलतारा चौक, सीपत रोड में बाउंड्री वाल किया हुआ शीश्र बेचना है सम्पर्क करें- 9425545552 (37006)

बेचना है-रायपुर रोड, हाईकोर्ट के सामने, मेन रोड से 50 मीटर अन्दर न्यू एयरपोर्ट रोड, बोदरी में 50*200= 10000 वर्गफीट व्यवसायिक डायवर्सन बाउन्ड्री वाल सहित प्लाट बेचना है। सम्पर्क करें-9300310774 (36975)

क्रिया

क्रिया- सिरिगट्टी स्थित इण्डस्ट्री में मंथली बेसिस पर 3 टन, 12 टन क्षमता वाली गाड़ियां फिटिंग पर चाहिए भाड़ा प्रति किलोमीटर के आधार पर इच्छुक वाहन मालिक सम्पर्क करें- 9302668010 (477)

बेचना है

बेचना है-नेहरू नगर प्राईम लोकेशन अर्चना विहार के पास दो मंजिला 3BHK स्वतंत्र पूर्व दिशा मकान एवं सकरी NH से लगा T&C कालोनी में प्लाट एवं 2BHK नवनिर्मित स्वतंत्र मकान बेचना है। सम्पर्क- घोष एसोसिएट्स 9425220523, 9827875257 (36967)

बेचना है-बिलासपुर में सर्व सुविधा युक्त T&C कॉलोनी में 4BHK मकान बेचना है केवल खरीददार ही सम्पर्क करें- 9617881169, 96697 15765 (37004)

बेचना है-उसलापुर स्टेशन के सामने जहाँ पर स्टेशन बनना है 22*50= 1100 वर्गफीट के दो डायवर्टेड प्लाट बेचना है फ्रेंड्स युवा कॉलोनी से लगे हुए इच्छुक व्यक्ति ही सम्पर्क करें- 7 6 1 0 7 9 8 4 8 9 (37025)

बेचना है-हर्ष- फिनक्ससिटी पूर्ण विकसित कालोनी वाई- 49, बीआर यादव नगर, बिजौर बिलासपुर विभिन्न साइज लेआउट प्लाट, 3BHK डुप्लेक्स बंगलो, 2/3BHK अपार्टमेंटल फ्लैट, T&C रेरा रजिस्टर्ड। सम्पर्क- एसके बिल्डर्स & डेवलपर्स 88394 55596, 7697644444 (36177)

बेचना है-बिलासपुर में गोकुल धाम में सर्व सुविधा युक्त 2BHK, 25*40= 1000 वर्ग फीट में बना हुआ नव निर्मित मकान 28 लाख रुपए में बेचना है सम्पर्क करें- 9340252857 (36988)

बेचना है-डायवर्टेड प्लांट 30*58 मेन रोड ऊपर मटियारी, बेलतारा चौक, सीपत रोड में बाउंड्री वाल किया हुआ शीश्र बेचना है सम्पर्क करें- 9425545552 (37006)

बेचना है-रायपुर रोड, हाईकोर्ट के सामने, मेन रोड से 50 मीटर अन्दर न्यू एयरपोर्ट रोड, बोदरी में 50*200= 10000 वर्गफीट व्यवसायिक डायवर्सन बाउन्ड्री वाल सहित प्लाट बेचना है। सम्पर्क करें-9300310774 (36975)

क्रिया

जैजपुर में नियमों के विपरीत डोलामाइट की माइनिंग, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

हरिभूमि न्यूज | बिलासपुर

जैजपुर तहसील के अकलसरा ग्राम पंचायत में नियम विपरीत की जा रही डोलामाइट माइनिंग के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई कर शासन और लीज ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। याचिका के मुताबिक अरविन्द सोनी को डोलामाइट खदान लीज पर प्राप्त हुई



थी। शासकीय शाला से करीब 700 मिटर दूर पर ही विस्फोटक लगाकर काम किया जा रहा है। यह माइनिंग सड़क से बिल्कुल करीब ही की जा रही है, स्कूल भी पास होने के कारण इसके भवन में कई जगह क्रैक आ गया है। इसी गाँव में सार्वजनिक उपयोग हेतु निर्धारित बैजंती नाले को भी सोनी ने पटवाकर एक धर्मकांड लगा लिया है। नाला पाटने के कारण ग्रामीणों की निस्तारी का साधन बंद हो गया है। इससे पहले जिला पंचायत सीईओ, जिला कलेक्टर और सीएम ऑफिस रायपुर तक लोगों ने शिकायत की। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो सऊ चंद्रा व अन्य ने एडवोकेट जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की। इसमें कहा गया कि लीज ठेकेदार ने पर्यावरण बचाने कोई पेड़ पौधे भी नहीं लगाए हैं। लीज की निर्धारित भूमि से ज्यादा बड़े इलाके में माइनिंग की जा रही है। भारी वाहनों से ग्राम पहुंच मार्ग भी जर्जर हो गया है। पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने शासन को विधिसम्मत निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद भी कलेक्टर ने अपनी जांच में शिकायत को खारिज कर दिया, जबकि पटवारी पंचनामे में शिकायत सही पाई गई थी। इसके बाद कोर्ट के निर्देश पर सुरक्षा निधि जमा करते हुए दोबारा जनहित याचिका लगाई गई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल को डीवी में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शासन और ठेकेदार को नोटिस जारी किया है।

शिक्षा के अधिकार में बच्चों को एडमिशन नहीं, सीटे भी घटाई गई

बिलासपुर। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत ईडब्ल्यूएस और बीपीएल वर्ग के बच्चों को सही तरीके से एडमिशन नहीं मिल पाने पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन और शिक्षा विभाग को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के नए नियम से आरटीई की सीटें घटने और एडमिशन नहीं होने या फर्जी एडमिशन पर भी कोर्ट ने जवाब देने कहा है। याचिका में इस बात का खास उल्लेख किया गया है कि बड़े निजी स्कूलों में आवेदनों को जानबूझकर निरस्त किया जा रहा है। इसके बाद इन सीटों पर डोनेशन और फीस लेकर ओपन भर्ती की जाती है। याचिका में कहा गया कि बड़े स्कूलों में कुल सीटों पर सिर्फ 3 प्रतिशत ही एडमिशन हो रहा है। यहां तक कि पिछले एक साल में प्रदेश में पूर्व की अपेक्षा लगभग सवा लाख कम एडमिशन हुए हैं। कोर्ट ने शासन और विभाग से जानकारी मांगी है कि आरटीई अंतर्गत आश्रित 25 प्रतिशत सीटों पर पिछले सालों में कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया है और कितनी सीटें खाली हैं? इसके साथ ही खाली सीटों को ओपन आधार पर भरा गया तो उसके लिए क्या नियम अपनाए गए? इस संबंध में कोर्ट ने शासन से भी पूरे स्ट्रक्चर की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि शिलाई के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सीवी मंगवंत राव ने शिक्षा के अधिकार को लेकर एक जनहित याचिका एडवोकेट देवर्षि सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में दायर की है। इस मामले में पूर्व में चार दर्जन निजी स्कूलों को पक्षकार बनाया गया था। पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस दिया था। यह मामला 2012 से कोर्ट में चल रहा है। साल 2016 में हाईकोर्ट ने विस्तार से इस बारे में निर्देश जारी किए थे लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने आदेश को ठीक से लागू नहीं किया। इसी शिकायत को लेकर एडवोकेट देवर्षि के माध्यम से फिर से याचिका दायर की गई है।

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन से रिपोर्ट मांगी

शराब घोटाला , त्रिपाठी की याचिका पर ईओडब्ल्यू को नोटिस

बिलासपुर। शराब घोटाले के मामले में आबकारी विभाग के निराले अफसर अरुणपति त्रिपाठी की किमिनल रिवीजन याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेच में हुई इस सुनवाई के बाद आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है। त्रिपाठी की ओर से हाईकोर्ट में किमिनल रिवीजन दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि धारा 9 के तहत इस तरह के मामलों में पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है, जो कि इस मामले में नहीं ली गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस केस की अगली सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। ज्ञात हो कि ध्यान रहे कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को शराब घोटाले के रिलेसिले में गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद उन्हें ईडी की विशेष अदालत में जेल भेज दिया था। त्रिपाठी ने विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में भी जमानत की मांग की, मगर राहत नहीं मिली। बाद में, हाईकोर्ट ने दोबारा जमानत याचिका लगाई गई, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।

भूमि अतिक्रमण पर बालको से जवाब तलब

बिलासपुर। बालको कंपनी ने कोरबा में कांकीट प्रोडक्शन के लिए बड़े पैमाने पर शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर अपना काम शुरू कर दिया है। नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे उत्पादन और

नियमों का उल्लंघन कर लगाया बैगिंग प्लांट

अतिक्रमण की चुनौती देते हुए पेश जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बालको प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका के मुताबिक बालको कंपनी ने कोरबा शांति नगर में कुलिंग टावर के ही करीब बैगिंग प्लांट शुरू किया है। यहां कांकीट का उत्पादन किया जा रहा है। इस इलाके में पहले से ही रहते आ रहे 87 परिवारों को विस्थापित करते हुए उनके व्यवस्थापन का इंतजाम किया गया था। इसी जंगल बाद में हुए सर्वे में 46 प्रभावित परिवार और सामने आए। इनके लिए बालको ने अब तक कुछ नहीं किया है। सामाजिक कार्यकर्ता डिलेन्द्र यादव ने पहले जो शिकायत की थी उस पर कोरबा कलेक्टर ने जांच समिति बनाई। जांच के बाद प्रतिवेदन में बताया गया कि बालको कंपनी कई हेक्टेयर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर अपनी परियोजना विस्तार को गति देता आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर डिलेन्द्र यादव व जितेन्द्र साहू ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

डीएमएफ घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने मनोज द्विवेदी, माया वारियर को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया

हरिभूमि न्यूज-रायपुर

डीएमएफ घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने कोरबा में तत्कालीन आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर माया वारियर तथा एनजीओ संचालक मनोज द्विवेदी को पूछताछ करने रिमांड पर लिया है। तीन दिन पूर्व सोमवार को जांच एजेंसी ने डीएमएफ घोटाला मामले में सूर्यकांत तिवारी तथा निर्वाचित आईएसएस सीमा चौरसिया को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार करने के साथ ही डीएमएफ में पूर्व में गिरफ्तार रानू साहू सहित तीनों को पूछताछ

करने गुरुवार तक रिमांड पर लिया है।

ईओडब्ल्यू के अफसरों से मिली जानकारी के मुताबिक डीएमएफ घोटाला मामले में उद्गम सेवा समिति के नाम से एनजीओ संचालित करने वाला मनोज द्विवेदी तथा आशा वारियर अहम कड़ी हैं। इस वजह से दोनों से पूछताछ करने विशेष कोर्ट से रिमांड ली गई है। रिमांड के दौरान अफसर जानने की कोशिश करेंगे कि डीएमएफ घोटाले की रकम अफसरों के साथ राजनेताओं तक कैसे पहुंचती थी। रकम पहुंचाने किस तरह से लिंक का उपयोग करते थे।

डीएमएफ घोटाला करने बना था सिंडिकेट

ईओडब्ल्यू के अफसरों को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक डीएमएफ घोटाले को अंजाम देने के लिए एक पूरा सिंडिकेट बना हुआ था। अफसरों तक सिंडिकेट के माध्यम से घोटाले की रकम पहुंचती थी। डीएमएफ घोटाला करने जो सिंडिकेट बनाए गए थे, उस सिंडिकेट में मनोज द्विवेदी सेतु का काम करता था।

इसके माध्यम से अफसरों तक पहुंचती थी रकम

अफसरों के अनुसार अफसरों के कहने पर खनन माफिया मनोज द्विवेदी के एनजीओ को पैसा देते थे। जांच के दौरान मनोज द्विवेदी के अकाउंट से 17 करोड़ रुपए लेने-देने होना पाया गया है। मनोज द्विवेदी आशा वारियर के साथ रानू साहू के बेहद करीबी थे। दोनों अफसरों को मालूम था कि मनोज एनजीओ संचालित करता है। इस वजह से अफसर खनन माफिया को मनोज के एनजीओ में पैसा देने के लिए कहते थे। खनन माफिया से मिले पैसों को मनोज अफसरों तक पहुंचाने का काम करता था।

इनके कहने पर मिलता था काम

जांच के दौरान पुलिस को रजनीकांत तिवारी के पास से एक डायरी मिली थी। डायरी की जांच करने पर पता चला कि सीमा चौरसिया तथा सूर्यकांत तिवारी जिन नामों का रिकमेंट करते थे, उन्हें ही डीएमएफ का काम मिलता था। इस वजह से डीएमएफ घोटाले में सीमा तथा सूर्यकांत को ईओडब्ल्यू ने आरोपी बनाया है।

60 प्रतिशत तक कमीशन मिलता था

डीएमएफ घोटाला में 60 प्रतिशत राशि की बंदरबांट होती थी। इस बात का उल्लेख रजनीकांत से जस्ट डायरी में हुआ है। जिन लोगों तक कमीशन की राशि पहुंचती थी, उनमें सीमा चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू से लेकर नेताओं तक के नाम शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसी रजनीकांत को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है।

दवाओं और खाद्य पदार्थों की जांच करने वाला एफडीए होगा अपडेट, हर जिले में अपना भवन और गाड़ियां

हरिभूमि न्यूज: रायपुर

दवाओं और विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों की जांच करने वाले खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को संसाधनों से लैस किया जाएगा। हर जिले में इनका अपना भवन और गाड़ियां होंगी। राज्य शासन ने अपने बजट में नवा रायपुर में आधुनिक लैब बनाने के लिए जमीन और मशीन खरीदी के लिए 378.80 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा लैब में मानव संसाधन की व्यवस्था के लिए 35 पद

सृजित किए गए हैं। राज्य शासन प्रदेश में गुणवत्ता पूर्ण दवाओं और खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर काफी गंभीर है। इसे ध्यान में रखते हुए इनकी जांच और निगरानी करने वाले एफडीए को सुविधा संपन्न बनाने की तैयारी की जा रही है। बजट में इन जिला कार्यालय के लिए अपना भवन बनाने के लिए 524.40 लाख रुपए का व्यय होगा। इस वर्ष 150 लाख का व्यय संभावित है। इसके साथ ही मैदानी अमले को सक्रिय रखने के लिए 10 नयी गाड़ियां खरीदने का प्रावधान भी किया गया है। बजट में

नवा रायपुर में आधुनिक सुविधाओं वालों इंटीग्रेटेड लैब बनाने के लिए जमीन खरीदी और भवन निर्माण के लिए भी 268 लाख रुपए खर्च होगा। लैब मानव संसाधन से सुसज्जित होगा। इसके लिए 35 पद सृजित किए गए हैं। वर्तमान में एफडीए का राज्य स्तर लैब का संचालन राजधानी में कालीबाड़ी के समीप संचालित होता है। आवश्यकता के हिसाब से कार्यालय काफी छोटा है और यहां जरूरतों के हिसाब से जांच की सुविधा नहीं मिल पाती है। सीमित संसाधन होने की वजह से जांच टीम को भी

भेजे गए सैपलों की रिपोर्ट के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। एफडीए के मैदानी टीम के पास अभी अपना कार्यालय नहीं होने की वजह से किसी प्रकरण में जब्त किए गए सामानों खुले में रखना मजबूरी होता है। कुछ ही जिलों के पास अपना भवन है यहां तक रायपुर जिले की एफडीए टीम का कार्यालय भवन भी लैब की बिल्डिंग में संचालित होगा। अपनी बिल्डिंग होने के बाद मैदानी अमले को जब्ती सामान और दस्तावेज सुरक्षित रखने में आसानी होगी।

सर्वप्रथम अत्याधुनिक

(अल्ट्रागार्डन) बर्न यूनिट

10 इंटेक्सिव
आइसोलेशन केयर
ग्लास केबिन,
हेपा फिल्टर/लेमिनर
फ्लो 100% जीवाणु
रहित ग्लास केबिन.

उ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त

कालड़ा बर्न एवं
प्लास्टिक कांस्ट्रक्टिफ सर्जरी सेंटर
आर.के.डी.के.सामने, चौबे कालोनी एवं पंचवटी
मार्कट, धमतरी रोड, कलर्स मॉल के पास, रायपुर
कॉल : 9827143060/8871003060
Ajay Adv.

Scooter बोले तो

ACTIVA

Honda RoadSync App

Smart TFT screen

Smart Key Technology

All New ACTIVA 110

All New ACTIVA 125

Scratch & Win* for Assured Gift

Exchange Bonus worth ₹2000/-*

Low ROI @ 7.99%**

Cashback of 5% up to ₹5000#

IDFC FIRST Bank Credit Card

HDFC BANK Credit Card

Limited Period Offers

For dealer details scan the QR Code

*Terms and conditions apply. #Cashback Offer is available on purchase of any Honda two wheeler model includes 5% cashback upto maximum of ₹5000 on EMI transactions using HDFC bank credit card and IDFC FIRST bank credit card through Pine Labs machines only. #The scheme is available in selected outlets only. #Cashback offer is valid until 31st March 2025. **The finance scheme is at the sole discretion of the financier, subject to its respective T&Cs. **The offers may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *Schemes of Scratch & Win with assured gift and ₹2000 Exchange Bonus on all models are offered by Authorised Main Dealers and Associate Dealers and can be availed on purchase of all models from Authorised Main Dealers and Associate Dealers. *This scheme is for both Finance & Cash Customers. *The offers are applicable in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh only. *Scheme can be withdrawn from the market without prior notice. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; Website: www.honda2wheelerindia.com; Customer Care: customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: **AKALTARA:** Bhagwati Honda - 9827520716, 9425229083; **AMBIKAPUR:** Mahamaya Honda - 7489027000, 7489026000, 7489025000; **Jaswani Honda** - 8358065000, 8358063000; **BAIKUNTHPUR:** Pramila Honda - 7000405012, 9754679867; **BARADWAR:** Ganpati Honda - 7974875687; **BILASPUR:** Dream Honda - 07752-400957, 07752-409057, 9926802408; **Maosaji Honda** - 07752-412020, 7024149881; **BILHA:** Sai Honda - 9179256022, 9827138322; **KAWARDHA:** Pratha Honda - 7400550099, 7400540099; **DHARAMJAGARH:** Harsh Honda - 9424180180; **DIPKA:** Kamal Honda - 9111144667; **JANJIGIR CHAMPA:** Gattani Honda - 07817-222396, 7694011206, 7694011208; **Shubh Honda (Baloda)** - 8574921111; **JASHPUR:** Deo Narayan Honda - 9406108464, 9425251702; **KHARSIA:** Balaji Honda - 8269515770; **KORBA:** Vishal Honda - 07759-222509, 9479025937, 7987973739; **Krishna Korba Honda** - 7747015377, 6232103020, 6232103021; **JP Honda (Hardi Bazar)** - 9826129114; **Ashwini Honda (Urga)** - 6232103023; **Bharat Honda (GevraBasti)** - 09301001739; **KOTA:** Prakash Honda - 9826417995; **KUNKURI:** Mansharam Honda - 8103798783; **LAILUNGA:** Atul Honda - 9424188280; **LORMI:** Mansi Honda - 9685010000; **MANENDRAGARH:** Harsh Honda - 9993883343; **MASTURI:** Rahul Honda - 9098619245, 7898410560; **PALLI:** Mahamaya Honda - 8770804342; **PAMGARH:** Gautam Honda - 8962109746; **PANDARIYA:** Shri Balaji Honda - 73993330099; **PATHALGAON:** Dinesh Honda - 9993199887; **PENDRA ROAD:** Dev Honda - 9752998221; **RAHOD:** Shri Balaji Honda - 9977311242; **RAIGARH:** Sharda Honda - 8103664400, 9300473589; **Shanti Auto Honda** - 9343609280, 9343609281; **RAJPUR:** Maa Mahamaya Honda - 9424259688; **RAMANUJGANJ:** Pankaj Honda - 9926158656; **RATAMPUR:** Sunil Honda - 9893354893; **SAKIT:** Maa Durga Honda - 9685927215; **SARAIKALI:** Pukhraj Honda - 8889798000; **SARANGARH:** Akshat Honda - 9406353035; **SARSIVA:** Kanisk Honda - 9575533947; **SHEORINARAYAN:** Arav Honda - 8109955535; **SITAPUR:** Akash Honda - 9617378301; **PRATAPUR:** Shri Banbhori Honda - 8120806101; **SURAJPUR:** Shri Om Honda - 9826774095, 9926684331; **TAKHATPUR:** Dream Honda - 9303005917, 8839264059; **TAPKARA:** Jindal Honda - 9406384666; **WADRUFNAGAR:** KP Auto - 9826881578; **BILASPUR SAKRI:** Dream Honda Branch - 9516661444; **BILASPUR DAYALBANDH:** Maosaji Honda Branch - 07752-417070, 417171, 9109690484; **GAURELLA:** Shyam Honda - 7024806222; **AHIWARA:** Kabiram Honda - 8319225193; **Shree Sairam Honda (Risali)** - 0788 4067690, 8823050333; **DANTEWADA:** Ansh Honda - 7000396031; **NEHRU NAGAR:** Aan Honda - 8581020999; **MUNGELI:** S. Mansi Honda - 9685010000.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutional@honda2wheelerindia.com